@Kamal.Sandesh KamalSandeshLive www.kamalsandesh.org kamal.sandesh @KamalSandesh

कमल संदेश

'एनडीए सरकार में बिहार में विकास की नई गाथा लिखी गई है'

वर्ष-15, अंक-21 01-15 नवम्बर, 2020 (पाक्षिक) ₹20

राजग का संकल्प
आत्मनिर्भर बिहार

बेतिया (बिहार) में एक चुनावी सभा के दौरान जनाभिवादन स्वीकार करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

पश्चिम बंगाल स्थित बागडोगरा में प्रसिद्ध समाज सुधारक ठाकुर पंचानन बरमा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

पश्चिम बंगाल स्थित आनंदमयी कालीबाड़ी मंदिर में पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद ग्रहण करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

बिहार स्थित पटना साहिब गुरुद्वारा में प्रार्थना करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

आरा (बिहार) में एक कार्यकर्ता सम्मेलन में 'सशक्त पंचायत-समर्थ बिहार' पुस्तिका का विमोचन करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सह संपादक
संजीव कुमार सिन्हा
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
भोला राय

डिजिटल मीडिया
राजीव कुमार
विपुल शर्मा

सदस्यता एवं वितरण
सतीश कुमार

इ-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
फोन: 011-23381428, फैक्स: 011-23387887
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 बिहार के लोग ठान चुके हैं, एनडीए को फिर जिताना जरूरी है: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार के डेहरी (सासाराम), गांधी मैदान, गया और हवाई अड्डा मैदान, भागलपुर में 23 अक्टूबर 2020 को आयोजित विशाल जन-सभाओं को संबोधित किया और कहा कि बिहार ने चुनाव से काफी...

श्रद्धांजलि

'राजनीति के अजातशत्रु'–कैलाशपति मिश्र 23

भाजपा नेता व बिहार सरकार में मंत्री विनोद कुमार सिंह नहीं रहे 23

वैचारिकी

राष्ट्र की सुरक्षा के प्रश्न को सर्वोपरि महत्त्व दिया जाए 21

लेख

कृषि सुधार विधेयकों से किसानों को क्रांतिकारी बदलावों की उम्मीद – राजकुमार चाहर 32

अन्य

गरीब किसानों और ग्रामीणों के हितों को मोदी सरकार ने हमेशा सुनिश्चित किया 16

राज्यों को पूंजीगत परियोजनाओं के लिए 12,000 करोड़ रुपये का ब्याज-मुक्त कर्ज देगी केन्द्र सरकार 19

जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं: नरेन्द्र मोदी 24

प्रधानमंत्री ने एफएओ की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 75 रुपये का सिक्का जारी किया 25

सड़कें और पुल किसी भी राष्ट्र की जीवन-रेखा हैं: राजनाथ सिंह 27

देश की खातिर अब तक 35,398 पुलिसकर्मियों ने न्योछावर किए अपने प्राण: अमित शाह 28

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आंध्र प्रदेश में 16 एनएच परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया 29

09 'आत्मनिर्भर बिहार' की ओर

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 22 अक्टूबर, 2020 को पटना में भारतीय जनता पार्टी का बिहार...

10 एनडीए सरकार में राज्य में विकास की नई गाथा लिखी गई है: जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 20 अक्टूबर, 2020...

14 नागरिकता संशोधन कानून के तहत पात्रता वाले लोगों को भारत की नागरिकता मिल कर रहेगी...

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 19 अक्टूबर 2020...

18 आर्थिक विकास तेज करने के लिए 73,000 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन...

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 12 अक्टूबर को...

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, बी-2, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.)-201307 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

सोशल मीडिया से

नरेन्द्र मोदी

देश के सामने एक और बड़ी चुनौती है- भ्रष्टाचार का वंशवाद, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हुआ भ्रष्टाचार। यह स्थिति देश के विकास में बहुत बड़ी बाधा है। मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि 'भारत बनाम भ्रष्टाचार' की लड़ाई में भ्रष्टाचार को परास्त करते रहें।

जगत प्रकाश नड्डा

कांग्रेस का अहंकार नहीं गया है। उन्हें लगता है कि देश में उनके परिवार के अलावा कोई प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता। देश की सेवा कोई और करे, ये उन्हें पसंद नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश और बिहार आगे बढ़े, तो एनडीए को बिहार में जिताइए।

अमित शाह

कोरोना के समय नरेन्द्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने एक संवेदनशील सरकार कैसी होती है वो दर्शाया। मोदी सरकार द्वारा छठ पूजा तक गरीबों को मुफ्त राशन, किसानों के खातों में 6000 रुपये, नीतीश जी द्वारा सभी प्रवासी मज़दूरों के रहने की व्यवस्था, उनके आने का टिकट, सभी को एक किट और एक हजार रुपए दिए।

राजनाथ सिंह

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का यह संकल्प है कि देश के हर गरीब के पास 2022 तक अपना एक पक्का मकान हो। आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसान सम्मान निधि के अन्तर्गत सीधे किसानों के खाते में छह हजार रुपये भेजे जा रहे हैं। किसानों की सबसे बड़ी हितैषी है यह सरकार।

बी. एल. संतोष

कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। हम पूरी तरह से सहमत हैं। कल वह दिन था जब उनकी पार्टी के मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने अपने भाषण में भाजपा प्रत्याशी और दलित महिला श्रीमती इमरती देवी को 'आइटम' कहा।

नितिन गडकरी

ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं के बेहतर नियोजन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड का वितरण शुरू। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों का सशक्तिकरण करने के लिए भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। स्वामित्व योजना से ग्रामवासियों को न केवल अपनी आवासीय संपत्ति का मालिकाना हक़ मिलेगा, बल्कि गांवों में संपत्ति को लेकर जो वर्तमान स्थिति है, उसको ठीक करने का एक अनूठा प्रयास भी होगा।

'आत्मनिर्भर बिहार' का साकार होता स्वप्न

बिहार में चुनावी बिगुल बजते ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू हो गई और विधानसभा चुनावों में चल रहे प्रचार में लोग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को अपना भारी समर्थन देने निकल पड़े हैं। श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राजग सरकार को बिहार में लालू काल के 15 वर्ष तक चले लंबे 'जंगलराज' को समाप्त कर शांति, प्रगति, सुशासन एवं विकास के नए युग को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। पिछले 15 वर्षों में भ्रष्टाचार, अपराध-तंत्र, जातिवाद, कुशासन, लोकतांत्रिक आवाजों का दमन एवं विकास विरोधी नीतियों के चक्र से निकालकर बिहार के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। प्रदेश की अनेक उपलब्धियों को जनता महसूस कर रही है जिसे सुशासन, बदली हुई कार्य-संस्कृति, विकास एवं कानून व्यवस्था की पुनर्बहाली में प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। एक ओर जहां बिहार तीव्र विकास की दौड़ में शामिल हो चुका है, वहीं दूसरी ओर विकास के विभिन्न मानदंडों पर इसकी उपलब्धियां भविष्य के लिए आशा जगा रही हैं।

बिहार की जनता राजद काल के वो 15 वर्षों के 'जंगलराज' को कभी नहीं भूल सकती, जो अब भी एक दुःस्वप्न की भांति उनकी स्मृतियों को झकझोरती रहती है। परंतु ऐसा लगता है कि राजद अपने पुराने जनविरोधी नीतियों से कोई सबक नहीं सीखना चाहती, अन्यथा वो लोकतंत्र विरोधी एवं अराजकता एवं हिंसा में विश्वास करने वाली ताकतों से कभी हाथ नहीं मिलाती। इसका कम्युनिस्टों के साथ गठबंधन प्रदेश की शांतिप्रिय जनता के लिए एक चेतावनी है। राजद का 'गुंडाराज' एवं कम्युनिस्टों का 'बंदूकराज' का गठजोड़ प्रदेश को फिर से हिंसा एवं अराजकता के दलदल में डाल सकता है। साथ ही, राजद वंशवादी राजनीति का एक ऐसा उदाहरण है जो कांग्रेस की वंशवादी राजनीति के साथ 'नीम पर करेला चढ़ा' साबित हो रहा है। वास्तव में देखा जाए तो राजद-कांग्रेस-कम्युनिस्ट गठजोड़ लोकतंत्र विरोधी एवं विकास विरोधी ताकतों का ऐसा सिद्धांतहीन गठजोड़ है जो किसी भी हाल में सत्ता में आकर प्रदेश का दोहन करना चाहती है। ऐसे गठजोड़ को राष्ट्रीयता एवं लोकतंत्र को पूजने वाली बिहार की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी।

पिछले 15 वर्षों में भ्रष्टाचार, अपराध-तंत्र, जातिवाद, कुशासन, लोकतांत्रिक आवाजों का दमन एवं विकास विरोधी नीतियों के चक्र से निकालकर बिहार के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

यदि राजग शासन के पिछले 15 वर्षों की तुलना लालू काल के 15 वर्षों से की जाए, तब तस्वीर एकदम से स्पष्ट हो जाती है। यदि सकल घरेलू उत्पाद विकास दर पर नजर डाली जाए, तो पिछले 15 वर्षों में यह मात्र 3.19 प्रतिशत से बढ़कर 11 प्रतिशत से भी अधिक हो गई है तथा कृषि विकास दर 2.35 प्रतिशत से बढ़कर 8.50 प्रतिशत हो चुकी है। प्रति व्यक्ति आय भी केवल रु. 8000 से बढ़कर अब रु. 43,822 हो गई है। एक ओर जहां प्रदेश का 100 प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है, वहीं दूसरी ओर राजग शासन में 96 प्रतिशत सड़कों का पक्कीकरण हो चुका है। प्रदेश ने न केवल व्यापक कृषि विकास देखा है, बल्कि औद्योगिक विकास दर भी 17 प्रतिशत है, जिसे किसी भी पैमाने पर उत्कृष्ट कहा जा सकता है। इन अद्भुत उपलब्धियों के अलावा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का बिहार से विशेष लगाव रहा है, जो उनके द्वारा बिहार पर विशेष ध्यान देने से स्पष्ट दिखाई देता है। प्रदेश के लिए अपने विशेष लगाव के कारण उन्होंने न केवल 1.25 लाख करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया, बल्कि 40,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता बिहार के विकास के लिए उपलब्ध कराई। इसका परिणाम यह है कि आज बिहार में उच्चस्तरीय अवसंरचना का निर्माण हो रहा है जिससे आने वाले दिनों में विकास की नई गाथाएं लिखी जाएंगी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' के आह्वान से प्रेरणा लेते हुए बिहार भाजपा ने 'आत्मनिर्भर बिहार' लिए स्वयं को प्रतिबद्ध किया है। बिहार में इस आह्वान को जन-जन का भारी जनसमर्थन मिल रहा है जिसे देखकर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने ठीक ही कहा है कि बिहार में लोग राजग की सरकार पुनः बनाने का मन बना चुके हैं। आज जब बिहार शांति, प्रगति, सुशासन एवं विकास के पथ पर अबाध गति से चलने को कृत-संकल्पित है तथा राजग को जन-जन का भारी समर्थन मिल रहा है, ऐसे में 'आत्मनिर्भर बिहार' का स्वप्न साकार होता दिख रहा है। ■

shivshakti@kamalsandesh.org

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन
विशाल जनसभा-भागलपुर

बिहार के लोग ठान चुके हैं एनडीए को फिर जिताना जरूरी है: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार के डेहरी (सासाराम), गांधी मैदान, गया और हवाई अड्डा मैदान, भागलपुर में 23 अक्टूबर 2020 को आयोजित विशाल जन-सभाओं को संबोधित किया और कहा कि बिहार ने चुनाव से काफी पहले ही एनडीए सरकार बनाने का निर्णय ले लिया है। सासाराम में मंच पर श्री मोदी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, बिहार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल, विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष श्री मुकेश सहनी और सासाराम से सांसद श्री छेदी पासवान भी उपस्थित थे। सासाराम की रैली से भाजपा के 12, जदयू के 12 और वीआईपी के 1 उम्मीदवार एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र से श्री मोदी की रैली से वर्चुअली जुड़े। गया में श्री मोदी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री श्री नित्यानंद राय, बिहार सरकार में मंत्री श्री प्रेम कुमार सहित कई एनडीए के वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। भागलपुर की रैली में मंच पर श्री मोदी के साथ मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार सहित एनडीए के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे।

श्री मोदी ने सर्वप्रथम केंद्र सरकार में मंत्री एवं गरीबों-दलितों के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले श्री राम विलास पासवान और गरीबों के उत्थान के लिए काम करने वाले श्री रघुवंश प्रसाद सिंह को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कोरोना जैसी बड़ी आपदा का डटकर मुकाबला करने और लोकतंत्र का पर्व मनाने के लिए बिहार की जनता को बधाई दी। उन्होंने कहा कि एनडीए का संकल्प है- बिहार को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं कि एनडीए को फिर जिताना जरूरी है। अगर बिहार में विरोध और अवरोध को ज़रा भी मौका मिला तो बिहार की गति और प्रगति दोनों धीमी पड़ जाएगी। इसलिए, नीतीश जी की अगुवाई में भाजपा, जेडीयू, हम और वीआईपी के गठबंधन यानी एनडीए को एक-एक वोट पड़ना चाहिए।

श्री मोदी ने कहा कि बिहार के लोग उन दिनों को भूल नहीं सकते जब सूरज ढलने का मतलब होता था, सब कुछ बंद हो जाना। आज बिजली है, सड़कें हैं, लाइटें हैं और सबसे बड़ी बात वो माहौल है जिसमें राज्य का सामान्य नागरिक बिना डरे रह सकता है, जी सकता है। आज के बिहार में लालटेन की जरूरत खत्म हो गई है। आज बिहार के हर गरीब के घर में बिजली का कनेक्शन है, उजाला है। ये वो दौर था जब लोग कोई गाड़ी नहीं खरीदते थे, ताकि एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनकी कमाई का पता न चल जाए। ये वो दौर था जब एक शहर से दूसरे शहर में जाते वक्त ये पक्का नहीं रहता था कि उसी शहर पहुंचेंगे या बीच में किडनैप हो जाएंगे। आज आप एक नए बिहार को बनते देख रहे हैं। बिहार में नई व्यवस्थाओं को बनते देख रहे हैं। आज बिहार में पीढ़ी भले बदल गई हो, लेकिन बिहार के नौजवानों को ये याद रखना है कि बिहार को इतनी

आज बिजली है, सड़कें हैं, लाइटें हैं और सबसे बड़ी बात वो माहौल है जिसमें राज्य का सामान्य नागरिक बिना डरे रह सकता है।

- बिहार भ्रष्टाचार मुक्त शासन का हकदार है। इसे कौन सुनिश्चित करेगा? खुद भ्रष्टाचार में लिप्त लोग या भ्रष्टाचारियों से लड़ने वाले लोग?
- बिहार विकास का हकदार है। विकास कौन सुनिश्चित करेगा? वो जिन्होंने केवल अपने परिवार का विकास किया या वो जो लोगों की सेवा में अपना परिवार भी भूल गए?
- बिहार रोजगार और उद्यमिता का हकदार है। ये कौन सुनिश्चित कर सकता है? वो जो सरकारी नौकरी देने को रिश्वत कमाने का जरिया मानते हैं या वो जो लोग बिहार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने और स्किल मैपिंग का काम कर रहे हैं?
- बिहार निवेश का हकदार है! ये कौन सुनिश्चित कर सकता है? वो जिन्होंने बिहार को जंगल-राज बना दिया या जो लोग बिहार को सुशासन दे रहे हैं, बिहार के विकास में जी जान से जुटे हैं।
- बिहार बेहतर कानून व्यवस्था का हकदार है। ये कौन सुनिश्चित करेगा? वो जिन्होंने गुंडों को खिलाया-पिलाया पाला या वो जिन्होंने गुंडों पर डंडा चलाया।
- बिहार अच्छी शिक्षा के अवसरों का भी हकदार है। क्या ये उन लोगों द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता, जिन्हें शिक्षा का महत्व ही नहीं पता या वो लोग जो आईआईटी, आईआईएम और एम्स को राज्य में लाने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं।

मुश्किलों में डालने वाले कौन थे। जिन लोगों ने एक-एक सरकारी नौकरी को हमेशा लाखों-करोड़ों रुपए कमाने का जरिया माना, जिन लोगों ने सरकारी नियुक्तियों के लिए बिहार के नौजवानों से लाखों की रिश्वत खाई, वो फिर बढ़ते हुए बिहार को ललचाई नजरों से देख रहे हैं। वो दिन जब सरकार चलाने वालों की निगरानी में दिन-दहाड़े डकैती होती थी, हत्याएं होती थीं, रंगदारी वसूली जाती थी, वो दिन जब घर की बिटिया, घर से निकलती थी, तो जब तक वापस न आ जाए माता-पिता की सांस अटकी रहती थी। आज बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थान खोले जा रहे हैं। यहां बोधगया में भी तो आईआईएम खुला है जिस पर करीब-करीब एक हजार करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वरना बिहार ने वो समय भी देखा है, जब यहां के बच्चे छोटे-छोटे स्कूलों के लिए तरस जाते थे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि गया जी का ये पूरा क्षेत्र भारत के ज्ञान, आस्था और अध्यात्म का केंद्र रहा है। ये कितनी बड़ी बिडंबना है कि जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उस धरती को नक्सली हिंसा और जघन्य हत्याकांडों में झोंक दिया गया। बीते वर्षों में बिहार के इस हिस्से को नक्सलियों के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं।

श्री मोदी ने कहा कि कोरोना के इस समय में भी गरीबों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एनडीए सरकार ने काम किया है। जहां कभी गरीब का राशन, राशन की दुकान में ही लुट जाता था, वहां कोरोना काल में गरीबों को मुफ्त राशन मिला है। शहरों में जो रेहड़ी, ठेला, चलाने वाले साथी हैं, उनके लिए भी बैंकों से आसान ऋण सुनिश्चित कराया जा रहा है ताकि वो अपना काम फिर शुरु कर सकें। गरीब भूखा ना सोए, त्योहार ठीक से मना सके, दीवाली और छठ पूजा ठीक से मना सके, इसके लिए मुफ्त अनाज की व्यवस्था की गई है। इसी कोरोना के दौरान करोड़ों गरीब बहनों के खाते में सीधी मदद भेजी गई, मुफ्त गैस सिलेंडर की व्यवस्था की गई।

उन्होंने कहा कि देश जहां संकट का समाधान करते हुए आगे बढ़ रहा है, ये लोग देश के हर संकल्प के सामने रोड़ा बनकर खड़े हैं। देश ने किसानों को बिचौलियों और दलालों से मुक्ति दिलाने का फैसला लिया तो ये बिचौलियों और दलालों के पक्ष में खुलकर मैदान में हैं। जब देश की रक्षा के लिए राफेल विमानों को खरीदा गया, तब भी ये बिचौलियों और दलालों की भाषा बोल रहे थे। मंडी और एमएसपी का तो बहाना है, असल में दलालों और बिचौलियों को बचाना है। याद कीजिए, लोकसभा चुनाव से पहले जब किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसे देने का काम शुरु हुआ था, तब इन्होंने कैसे भ्रम फैलाया था। ये एनडीए की ही सरकार है जिसने किसानों को लागत का डेढ़ गुना एमएसपी देने की सिफारिश लागू की थी। ये एनडीए की ही सरकार है जिसने सरकारी खरीद केंद्र बनाने और सरकारी खरीद, दोनों पर बहुत जोर दिया है। आज देश की जनता, देश के किसान, देश के नौजवान देख रहे हैं कि इन लोगों के लिए देशहित नहीं, दलालों का हित ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए जब-जब, बिचौलियों और दलालों

पर चोट की जाती है, तब-तब ये तिलमिला जाते हैं, बौखला जाते हैं। जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल-370 हटने का इंतजार देश बरसों से कर रहा था या नहीं। ये फैसला एनडीए की सरकार ने लिया, लेकिन आज ये लोग इस फैसले को पलटने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो आर्टिकल-370 फिर लागू कर देंगे। इनका दुस्साहस देखिए! इतना कहने के बाद भी ये लोग बिहार के लोगों से वोट मांगने की हिम्मत दिखा रहे हैं। जो बिहार अपने बेटे-बेटियों को सीमा पर देश की रखवाली के लिए भेजता है, क्या ये उसकी भावना का अपमान नहीं है? भारत की जांबाज सेना आतंकियों पर कोई कार्रवाई करे, सरहद पर तिरंगे की शान बढ़ाए, ये लोग विरोध में हैं। सुप्रीम कोर्ट अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने को कहे, ये लोग विरोध में हैं। राष्ट्रहित में कोई भी, कुछ भी फैसला ले, ये लोग विरोध में हैं। एनडीए के विरोध में आज जो लोग खड़े हैं, वो देशहित के हर फैसले का विरोध कर रहे हैं। जम्मू-कश्मीर से धारा-370 हटाने का फैसला हो, ये लोग विरोध में हैं। तीन तलाक के विरुद्ध कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को नए अधिकार देना हो, ये लोग विरोध में हैं।

श्री मोदी ने कहा कि बीते वर्षों में बिहार के गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी तक वो सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास किया गया है, जिन्हें पाना बहुत मुश्किल था। सुविधा के साथ-साथ बिहार के सभी वर्गों को अधिक से अधिक अवसर देने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को मिलने वाले आरक्षण को अगले 10 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। देश की शिक्षा व्यवस्था में तो बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से प्रेरणा लेते हुए अब कोशिश होगी कि मेडिकल, इंजीनियरिंग समेत सभी तकनीकी कोर्सेस को भी मातृभाषा में पढ़ाया जाए। आज छोटे किसानों, मछुआरों, पशुपालकों, सभी को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है। पीएम किसान योजना के तहत बिहार के 74 लाख किसान परिवारों के खाते में करीब 6 हज़ार करोड़ रुपए सीधे जमा कराए गए हैं। बिहार में स्वरोज़गार के अवसरों के लिए भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। आज मुद्रा योजना से गरीबों को, महिलाओं को, युवा उद्यमियों को, दुकानदारों को बिना गारंटी का ऋण मिल रहा है। गांवों में जो उद्यमी दीदियों के समूह हैं, उनको भी बैंकों से मिलने वाली सुविधा बढ़ाई गई है। कनेक्टिविटी, एनडीए की डबल इंजन की सरकार की प्राथमिकता रही है, पहचान रही है। आज बिहार के करीब-करीब हर गांव तक सड़क पहुंच रही है। नेशनल हाईवे चौड़े हो रहे हैं। बिहार की नदियों पर आज एक के बाद एक नए और आधुनिक पुल बन रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पहले राशन हो, गैस सब्सिडी हो, पेंशन हो, स्कॉलरशिप हो, हर जगह घोटाला-घपला चलता था। अब आधार, फोन और जनधन खाते से सब जुड़ चुका है। अब गरीब को उसका पूरा हक समय पर मिलना सुनिश्चित हुआ है। बिहार ने अब सुधार की राह में रफ्तार पकड़ ली है। इसे धीमा नहीं होने दिया जाएगा। अब हमारा फोकस इस पूरे क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने और तेज करने पर है। लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार की बहनों से मैंने कहा था कि आपको पीने के पानी की समस्या का समाधान देकर रहेंगे। इस दिशा में जल जीवन मिशन के तहत तेजी से काम चल रहा है।

श्री मोदी ने कहा कि सामान्य जन की सुविधा के लिए बिहार के युवा के रोज़गार और स्वरोज़गार के लिए बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी था। इसी सोच के साथ बिहार के लिए सवा लाख करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री पैकेज घोषित किया गया था। ■

तेजस्वी सूर्या ने भाजयुमो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला

बेंगलुरु से सांसद श्री तेजस्वी सूर्या ने 19 अक्टूबर, 2020 को भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। कार्यकर्ताओं ने गाजे-बाजे के साथ नई दिल्ली में उनका भव्य स्वागत किया।

श्री तेजस्वी ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के 14वें अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। भाजयुमो की निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद श्रीमती पूनम महाजन के सफल कार्यकाल पूर्ण होने पर श्री तेजस्वी ने पदभार ग्रहण किया। समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सर्वश्री अरुण सिंह और तरुण चुघ जी उपस्थित थे। उन्होंने नवनियुक्त भाजयुमो राष्ट्रीय अध्यक्ष को बधाई दी। पदभार ग्रहण करने पर श्री तेजस्वी ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह हर्ष और सम्मान का विषय है कि उन्हें विश्व के सबसे बड़े युवा संगठन युवा मोर्चा का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि भाजयुमो अध्यक्ष की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है। यह कोई लाभ का पद नहीं, बल्कि परीक्षा है। यह न ही केवल एक अवसर है, बल्कि एक चुनौती भी है। हमें मोदी सरकार की हर योजना अंतिम व्यक्ति तक पहुंचानी है। भारतीय जनता युवा मोर्चा पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु में लोकतंत्र को बहाल करने के लिए कड़ी मेहनत करेगा।

श्रीमती पूनम महाजन ने नवनिर्वाचित भाजयुमो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेजस्वी सूर्या को बधाई दी। ■

'आत्मनिर्भर बिहार' की ओर

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 22 अक्टूबर, 2020 को पटना में भारतीय जनता पार्टी का बिहार संकल्प-पत्र—2020 जारी किया। इस पत्र में पांच सूत्र, एक लक्ष्य व 11 संकल्प की बात की गई है। यह बिहार के विकास का विजन डॉक्युमेंट है। इस अवसर पर भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री एवं बिहार प्रदेश भाजपा प्रभारी श्री भूपेंद्र यादव, बिहार भाजपा विधानसभा चुनाव प्रभारी श्री देवेंद्र फड़णवीस, भाजपा बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल एवं बिहार संकल्प-पत्र समिति के अध्यक्ष और कृषि मंत्री डॉ. प्रेम कुमार सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। संकल्प-पत्र जारी करते हुए श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं प्रदेश के सभी लोगों से एनडीए के पक्ष में मतदान के लिए अपील करती हूं। उन्होंने कहा कि श्री नीतीश कुमार पुनः अगले पांच साल के लिए मुख्यमंत्री बनेंगे और उनके नेतृत्व में बिहार प्रगतिशील और विकसित राज्य बनेगा।

भरोसे के 11 संकल्प

1. कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बिहार की एनडीए सरकार ने देश के सामने मिसाल रखी है। हमारा संकल्प है कि जैसे ही कोरोना का टीका आई.सी.एम.आर. द्वारा स्वीकृति के बाद उपलब्ध होगा, हर बिहारवासी का निःशुल्क टीकाकारण करवाएंगे।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषा की भूमिका को केंद्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीजी की सरकार ने महत्व दिया है। इस कड़ी में बिहार में हम मेडिकल, इंजीनियरिंग सहित तकनीकी शिक्षा को हिंदी भाषा में उपलब्ध करायेंगे।
3. एनडीए सरकार ने बिहार में 3.5 लाख शिक्षकों की नियुक्तियां की। इसको आगे बढ़ाते हुए आने वाले एक वर्ष में राज्य के सभी प्रकार के विद्यालय, उच्च शिक्षा के विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों में 3 लाख नए शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे।
4. भारत में इस वक्त आईटी कारोबार 177 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए हम बिहार को नेक्स्ट जेनरेशन आईटी हब के रूप में विकसित करके अगले 5 वर्षों में 5 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध करायेंगे।
5. एनडीए सरकार ने बिहार में 10 लाख समूहों के माध्यम से 120 करोड़ महिलाओं के जीवन में रोशनी पहुंचायी है। हमारा संकल्प है कि स्वयं सहायता समूहों तथा माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के माध्यम से 50,000 करोड़ की माइक्रो फाइनेंस से 1 करोड़ नयी महिलाओं को स्वावलंबी बनाएंगे।
6. हमारा संकल्प है कि 10 हजार चिकित्सक, 50 हजार पैरामेडिकल कर्मियों सहित राज्य में कुल 1 लाख लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी के अवसर प्रदान करेंगे। साथ ही, प्रधानमंत्री जी द्वारा दरभंगा, बिहार को दिए दूसरे 'अखिल भारतीय आरोग्य संस्थान (एम्स)' का संचालन 2024 तक सुनिश्चित करेंगे।
7. किसानों को बिचौलियों से मुक्त करने के लिए बाजार समिति की व्यवस्था को हमारी सरकार ने पहले ही खत्म किया है। सशक्त कृषि, समृद्ध किसान के संकल्प पर आगे बढ़ते हुए हम संकल्प लेते हैं कि धान तथा गेंहू के बाद अब दलहन की भी खरीद एम.एस.पी की निर्धारित दरों पर करेंगे।
8. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के संकल्प पर चलते हुए बिहार में एनडीए की सरकार ने गत 6 वर्षों में 28,33,089 आवास बनाये हैं। हम इसी प्रतिबद्धता के साथ यह संकल्प लेते हैं कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों के और 30 लाख लोगों को वर्ष 2022 तक पक्के मकान देंगे।
9. दुग्ध उत्पादन को लेकर कोऑपरेटिव तथा कोम्फेड को प्रोत्साहित करेंगे तथा प्रोसेसिंग के क्षेत्र में निजी निवेश के लिए सुगमता प्रदान कर 2 वर्षों में निजी तथा कोम्फेड आधारित 15 नए प्रोसेसिंग उद्योग खड़े करेंगे।
10. प्रधानमंत्री जी द्वारा मत्स्य संपदा योजना को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार अगले 2 वर्षों में इनलैंड यानी मीठे पानी में पलने वाली मछलियों के उत्पादन में राज्य को देश का नम्बर एक राज्य बनाएगी।
11. बिहार के 1000 नए किसान उत्पाद संघों (एफ.पी.ओ) को आपस में जोड़कर राज्य भर के विशेष फसल उत्पाद जैसे मक्का, फल, सब्जी, चुड़ा, मखान, पान, मसाला, शहद, मेंथा, औषधीय पौधों का सप्लाई चेन विकसित करेंगे। इससे प्रदेश में 10 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे। ■

एनडीए सरकार में राज्य में विकास की नई गाथा लिखी गई है: जगत प्रकाश नड्डा

> “बिहार की जनता अब जागरुक हो गई है। वह जानती है कि अब बिहार में लालटेन राज नहीं चलेगा, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का एलईडी राज चलेगा। अब बिहार में लूट राज और गुंडाराज नहीं, क़ानून का राज चलेगा। बाहुबल का राज नहीं, विकास बल का राज चलेगा।”

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 20 अक्टूबर, 2020 को बिहार में महर्षि विश्वामित्र की धरती बक्सर और बाबू वीर कुवंर सिंह की धरती आरा में आयोजित विशाल जनसभाओं को संबोधित किया और राज्य की जनता से ‘विकास राज’ को चुनने का आह्वान करते हुए भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनाने की अपील की। मंच पर श्री नड्डा के साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल और क्षेत्र के सभी प्रत्याशी उपस्थित थे। श्री नड्डा ने कहा कि बिहार की तस्वीर बिलकुल साफ़ है। राज्य की जनता ने प्रदेश में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास के प्रति समर्पित एनडीए सरकार बनाने का निर्णय ले लिया है।

श्री नड्डा ने कहा कि बिहार में पहले कांग्रेस-आरजेडी द्वारा केवल जातिवाद, धर्म, भाई-भतीजावाद की राजनीति की जाती थी लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश की राजनीतिक संस्कृति को बदलते हुए इसे सरकार के रिपोर्ट कार्ड से जोड़ दिया। चुनाव में जनता को वोट उस पार्टी के पक्ष में डालना चाहिए जिन्होंने पहले विकास करके दिखाया है, उन्हें नहीं दिया जाना चाहिए जिन्होंने पहले तो कुछ किया नहीं लेकिन चुनाव आते ही झूठे वादों और प्रलोभनों की राजनीति करने लगते हैं।

आरजेडी पर प्रहार करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि राजद के पोस्टर में केवल तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे, लालू यादव जी दिखाई नहीं दे रहे। लालू यादव जी की तस्वीर को पोस्टर से उनके बेटे ने ही गायब कर दिया। गायब इसलिए किया क्योंकि बिहार की जनता अब जागरुक हो गई है। वह जानती है कि अब बिहार में लालटेन राज नहीं चलेगा, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का एलईडी राज चलेगा। अब बिहार में लूट राज और गुंडाराज नहीं, क़ानून का राज चलेगा। बाहुबल का राज नहीं, विकास बल का राज चलेगा।

श्री नड्डा ने कहा कि 2015 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपये विशेष पैकेज की घोषणा की थी। प्रधानमंत्रीजी ने अपने वादे को पूरा करते हुए बिहार को विशेष पैकेज के 1.25 लाख करोड़ रुपये तो दिए ही, इसके अतिरिक्त उन्होंने राज्य में अन्य परियोजनाओं में 40,000 करोड़ रुपये और दिए। प्रधानमंत्रीजी ने बिहार को किसान कल्याण के लिए लगभग 3,094 करोड़ रुपये, शिक्षा के लिए 1,000 करोड़, स्किल डेवलपमेंट के लिए 1,550

करोड़, स्वास्थ्य के लिए 600 करोड़ (पटना में अस्पताल के लिए 5000 करोड़ रुपये और दरभंगा में एम्स के लिए 1200 रुपये अलग से), बिजली के लिए 16,130 करोड़, सड़क के लिए 13,820 करोड़, राजमार्गों के विकास के लिए 54,713 करोड़, रेलवेज के लिए 8,870 करोड़, हवाई अड्डे के विकास के लिए 2,700 करोड़, डिजिटल बिहार के लिए 449 करोड़, पेट्रोलियम एवं गैस के लिए 21,476 करोड़ और पर्यटन के विकास के लिए 600 करोड़ रुपये दिए गए। इसके अतिरिक्त बिहार में अर्बन डेवलपमेंट के लिए 545 करोड़ रुपये, फिशरीज के लिए 152 करोड़ तथा पशुपालन और डेयरी के लिए 94 करोड़ रुपये अलग से दिए गए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व केंद्र की भाजपा-नीत एनडीए सरकार जो कहती है, उससे ज्यादा करके दिखाती है।

श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश को एकजुट करते हुए जिस तरह कोरोना के खिलाफ निर्णायक जंग का एलान किया, वह अभूतपूर्व है। उन्होंने मानवता की सेवा और जन-कल्याण के साथ-साथ आर्थिक चक्र को भी गति दी। उन्होंने 20 करोड़ महिला जन-धन खाताधारकों को तीन किस्तों में 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी। दिव्यांगों, बुजुर्गों और विधवाओं को भी एक-एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी गई। देश के 8.62 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि की किस्तें दी गई। किसान सम्मान निधि की एक और क़िस्त आने वाली है। देश के 80 करोड़ लोगों को मार्च से दिवाली-छठ तक मुफ्त राशन की व्यवस्था भी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने की। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 8 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुफ्त गैस सिलिंडर दिए, उद्योगों की चिंता की और एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर पर एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया।

श्री नड्डा ने कहा कि पूरे देश में 36 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब का वितरण किया गया जबकि बिहार में डेढ़ करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब वितरित किये गए। इसी तरह स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश में जहां 11 करोड़ से अधिक इज्जत घर बने, वहीं बिहार में 1.28 करोड़ इज्जत घरों का निर्माण किया गया। सौभाग्य योजना के तहत देश के 2.06 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाई गई जबकि बिहार में 29.59 लाख घर रोशन हुए। बिहार में मोदी सरकार ने 11 नए मेडिकल कॉलेजों की मंजूरी दी तो देश में 70 मेडिकल कॉलेज खोले गए। वह दिन दूर नहीं जब देश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्रीजी ने धारा 370 को ख़त्म कर जम्मू-कश्मीर में विकास की बयार बहाई है। उन्होंने अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। कांग्रेस ने तो इसे अटकाने, लटकाने और भटकाने के न जाने कितने जतन किये थे। हमारी सरकार ने ट्रिपल तलाक को बैन कर मुस्लिम महिलाओं को सम्मान से जीने का हक़ दिया।

श्री नड्डा ने कहा कि जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है तो मैं इनकी हरकतों को देख भी रहा हूं और अचरज भी कर रहा हूं। देशद्रोही हरकतें इनका स्वभाव बन गई है। कांग्रेस को देश की जनता ने बुरी तरह से नकार दिया है। उसकी ऐसी स्थिति हो गई है कि अब वह विपक्ष में भी बैठने के लायक नहीं रह गई है। उनके पास बताने को कोई उपलब्धि नहीं है, इसलिए ये लोग चुनाव तो बिहार में लड़ रहे हैं लेकिन गुणगान पाकिस्तान का कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान को शाबासी दे रहे हैं और पाकिस्तान का गुणगान करने वालों में सबसे आगे हैं राहुल गांधी। कोविड से जंग में सारी दुनिया जहां प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सराहना कर रही है वहीं राहुल गांधी पाकिस्तान के कोविड की चर्चा कर रहे हैं। जो भाषा अलगाववादी और पाकिस्तान की है, वही भाषा राहुल गांधी बोल रहे हैं। यहां तक कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र संघ को भारत के खिलाफ धारा 370 के उन्मूलन पर सौंपे डोजियर में राहुल गांधी के बयानों की चर्चा की।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश को एकजुट करते हुए जिस तरह कोरोना के खिलाफ निर्णायक जंग का एलान किया, वह अभूतपूर्व है।

कांग्रेस के एक और नेता पी. चिदंबरम ने तो खुल्लम-खुल्ला कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार आएगी तो जम्मू-कश्मीर में फिर से धारा 370 को बहाल किया जाएगा। अरे चिदंबरम जी, आपकी सरकार तो छोड़ो, भारत की जनता अब इतनी जागरुक हो गई है कि आपको वह विपक्ष में बैठने के लायक भी नहीं छोड़ेगी। कांग्रेस के एक और नेता शशि थरूर ने पाकिस्तान के मंच पर जाकर भारत का अपमान किया और पाकिस्तान की तारीफ़ की। ये है राष्ट्रभक्त कांग्रेस पार्टी। जब-जब देश में या देश के किसी राज्य में चुनाव आता है, कांग्रेस के नेता अलग-अलग राग अलापना शुरू कर देते हैं। कांग्रेस के एक नेता थे मणिशंकर अय्यर जो पाकिस्तान जाकर कहते हैं कि मोदी से बचाओ। ये हैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रभक्त नेता।

पाकिस्तान और चीन पर निशाना साधते हुए श्री नड्डा ने कहा कि पाकिस्तान और चीन अब जान गए हैं कि भारत की ओर यदि आंख उठाकर किसी ने देखा तो उसे नेस्तोनाबूद कर दिया जाएगा। आज भारत में घुसपैठ करने वाले आतंकियों की एक ही सजा है और वह है सजा ए मौत। आज चीन में खलबली इसलिए मची हुई है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख की सीमा तक विगत छः वर्षों में 4,700 किलोमीटर सड़क बनाकर पूरे बॉर्डर एरिया को कवर कर लिया है। सीमा पर 14,000 से ज्यादा फोरलेन ब्रिज बन कर तैयार हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने मनाली से लेह को जोड़ने वाली अटल टनल को राष्ट्र को समर्पित किया है।

श्री नड्डा ने कहा कि राजद के राज में अपराध, खौफ और अराजकता का साम्राज्य छाया हुआ था। ये वही आरजेडी है जिसकी सरकार में दलित डीएम को गाड़ी से उतारकर जान ले ली गई थी। ये वही आरजेडी है, जिसके शासन में शहाबुद्दीन ने राज्य के वर्तमान डीजीपी पर गोली चलाई थी। शहाबुद्दीन तब तक जेल नहीं गया जब तक सूबे में आरजेडी की सरकार बनी रही। श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने बाहुबल से विकास बल की यात्रा तय की है और राज्य में लॉ एंड ऑर्डर कायम हुआ है। श्री नीतीश कुमार ने बच्चियों को पुस्तकें व साइकिल दिया, कोरोना काल में सभी राशन कार्ड धारकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई और बिहार में विकास को एक नई गति दी। बक्सर में 10,400 करोड़ रुपये की लागत से 320 मेगावाट क्षमता के थर्मल पावर प्लांट बन रहा है, बक्सर में रामायण सर्किट पर काम चल रहा है, नेशनल हाइवे 84 को पटना से बक्सर तक जोड़ा जा रहा है और गंगा हाइवे को एक्सटेंड तक बक्सर तक किया गया है। ये सभी कार्य इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी हैं और राज्य में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार।

बेतिया और मोतिहारी

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 21 अक्टूबर, 2020 को बिहार में बड़ा रमना मैदान, बेतिया और महात्मा गांधी की कर्म भूमि मोतिहारी के गांधी मैदान में विशाल रैलियों को संबोधित किया और राज्य की जनता से विकास के प्रति समर्पित एनडीए की सरकार भारी बहुमत से बनाने की अपील की। मंच पर श्री नड्डा ने जी के साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल और क्षेत्र के सभी प्रत्याशी उपस्थित थे।

- **श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने बाहुबल से विकास बल की यात्रा तय की है और राज्य में लॉ एंड ऑर्डर कायम हुआ है।**
- **श्री कुमार ने बच्चियों को पुस्तकें व साइकिल दिया, कोरोना काल में सभी राशन कार्ड धारकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई और बिहार में विकास को एक नई गति दी।**

राजद पर कड़ा प्रहार करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि मैं रोजगार दूंगा। अरे तेजस्वी जी, आपके ही परिवार के शासन के चलते बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए राज्य से पलायन करना पड़ा और आपके पिताजी लालू प्रसाद यादव इसकी खुशी मनाते रहे। युवाओं को रोजगार दिलाने और गरीबों की मदद करने का काम किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किया है। विपक्ष के गठबंधन की एक घटक दल है माले। ये वही टुकड़े-टुकड़े गैंग वाले लोग हैं, देश को तोड़ने वाले लोग हैं जो हिंसा में विश्वास रखते हैं। इनका भारत की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में कोई विश्वास नहीं है और कांग्रेस की तो बात ही क्या की जाए?

विपक्ष पर प्रहार जारी रखते हुए श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष की दशा पर हमें दया भी आती है, उन पर करुणा भी आती है और चिंता भी होती है। राजद तो पहले ही हाइजैक हो चुकी है। 19 सीटों तो माले ने ले ली, 10 सीटें अपने साथियों को दिला दी और 12 सीटों पर तो राजद ने अपने कैंडिडेट बदलकर उनके लोगों को टिकट दे दिया है।

यदि ऐसी विध्वंसकारी ताकतें राजनीतिक दलों के माध्यम से मुख्यधारा में आई तो बिहार की क्या हालत होगी।

बिहारशरीफ (नालंदा) और लखीसराय

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 24 अक्टूबर, 2020 को बिहार में बिहारशरीफ (नालंदा) के श्रम कल्याण मैदान और लखीसराय के के.आर.के. हाई स्कूल ग्राउंड में आयोजित विशाल रैलियों को संबोधित किया और कहा कि बिहार की जनता का एनडीए को मिल रहे अपार जनसमर्थन से यह पहले ही चुनाव का नतीजा तय हो गया है कि प्रदेश में एक बार पुनः प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में और श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि हमें बिहार में विकास का नया आयाम जोड़ना है।

श्री नड्डा ने लालू राज के 15 वर्षों के जंगल राज पर निशाना साधते हुए कहा कि राजद के जंगलराज में अपराध, खौफ और अराजकता का साम्राज्य छाया हुआ था। उन्होंने कहा कि जिनके शासन में बिहार के सारे उद्योग-धंधे ठप्प पड़ गए थे, जिनके शासन में अपहरण उद्योग फलता-फूलता था, ऐसे लोग बिहार को रोजगार नहीं दे सकते, बिहार का भला नहीं कर सकते। नीतीश कुमार जी जानते थे कि राजद के साथ सुशासन नहीं आ सकता, केवल कुशासन ही आ सकता है, सुशासन तो केवल भारतीय जनता पार्टी के साथ ही आ सकता है। इसलिए नीतीश जी ने राजद से नाता तोड़ा।

श्री नड्डा ने कहा कि बिहार ने एनडीए के 15 वर्षों के शासनकाल में लालटेन युग से एलईडी युग, बाहुबल से विकास बल, कुशासन से सुशासन, भ्रष्टाचार युक्त शासन से भ्रष्टाचार मुक्त शासन और अविश्वास से विश्वास की यात्रा की है। हम बिहार में विकास की गति धीमी नहीं होने दे सकते।

• बिहार ने एनडीए के 15 वर्षों के शासनकाल में लालटेन युग से एलईडी युग, बाहुबल से विकास बल, कुशासन से सुशासन, भ्रष्टाचार युक्त शासन से भ्रष्टाचार मुक्त शासन और अविश्वास से विश्वास की यात्रा की है।

• प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है तो बिहार श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है।

औरंगाबाद और पूर्णिया

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 26 अक्टूबर, 2020 को बिहार में औरंगाबाद के गांधी मैदान और पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में आयोजित विशाल रैलियों को संबोधित किया और कहा कि जनता के जोश और उत्साह से यह पहले ही तय हो चुका है कि बिहार में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। बिहार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जारी विकास यात्रा के साथ चलना चाहता है, जंगलराज और अराजकता के साथ नहीं। मंच पर श्री नड्डा के साथ केंद्रीय मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद, क्षेत्र के सभी प्रत्याशी और एनडीए के सभी नेतागण उपस्थित रहे। दोनों रैलियों में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।

श्री नड्डा ने कहा कि यह चुनाव बिहार के विकास का चुनाव है। जहां एक ओर भारतीय जनता पार्टी हर सभा में विकास और विकास कार्यों की चर्चा करती है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस-आरजेडी-माले गठबंधन का जातिवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, तुष्टिकरण की राजनीति और अराजकता का इतिहास रहा है। उन्होंने राजद की 'तेल पिलावन, लाठी भजावन रैली' का जिक्र करते हुए कहा कि समाज को बांटकर चुनाव लड़ने का इनका इतिहास रहा है लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार आने के बाद देश की राजनीतिक संस्कृति बदल गई है और विपक्ष को भी विकास पर चर्चा करने को मजबूर होना पड़ा है।

श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है तो बिहार श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। एनडीए सरकार में बिहार में विकास की नई गाथा लिखी गई है। उन्होंने बिहार की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अगर आप विकास की गति को और तेज करना चाहते हैं, इसकी धार को अवरुद्ध करना नहीं चाहते तो पुनः भारी मतों से एनडीए की सरकार बिहार में बनाएं। ■

नागरिकता संशोधन क़ानून के तहत पात्रता वाले लोगों को भारत की नागरिकता मिल कर रहेगी: जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 19 अक्टूबर 2020 को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में विभिन्न समुदाय के प्रतिनिधियों के 'सामाजिक समूह' बैठक को संबोधित किया और पश्चिम बंगाल में अराजकता व हिंसा की राजनीति करने वाली तृणमूल कांग्रेस को जड़ से उखाड़ कर विकास के प्रति समर्पित भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का आह्वान किया। इससे पहले सिलीगुड़ी पहुंचने पर श्री नड्डा ने का पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता का श्री नड्डा के दौरे को लेकर उत्साह देखते ही बनता था। श्री नड्डा ने सिल्लीगुड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम नौका घाट में महान सुधारक डॉ पंचानन बर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके पश्चात् उन्होंने सिल्लीगुड़ी के प्रसिद्ध आनंदमयी कालीबाड़ी मंदिर में पूजा-अर्चना की। तत्पश्चात् उन्होंने एक कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित किया।

'सामाजिक समूह' बैठक में विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधि शामिल हुए और उन्होंने अपनी समस्याओं और मांगों को श्री नड्डा के समक्ष रखा। श्री नड्डा ने सभी प्रतिनिधियों को गंभीरतापूर्वक सुना और उन्हें आश्वस्त किया कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर इन सभी मुद्दों पर चिंतन-मनन होगा और इसका सर्वकालिक समाधान किया जाएगा। मंच पर श्री नड्डा के साथ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) श्री बी. एल. संतोष के साथ-साथ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पश्चिम बंगाल के प्रभारी श्री कैलाश विजयवर्गीय, पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष श्री दिलीप घोष, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मुकुल रॉय सहित पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता उपस्थित थे।

पश्चिम बंगाल में एक ओर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा है, जिसकी मूल नीति है 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास', वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी जी की टीएमसी सरकार है जिसका काम है फूट डालो और शासन करो।

श्री नड्डा ने कहा कि मुझे आपके दिल की बात समझ में आ गई है। जब मन और दिल मिलते हों तो भाषा की दीवार बीच में नहीं आती। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी सभी मांगों को निर्णायक मोड़ तक ले जाते हुए हम इसका सर्वकालिक समाधान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए कटिबद्ध है।

श्री नड्डा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में एक ओर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी है जिसकी मूल नीति है 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास', वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी जी की टीएमसी सरकार है जिसका काम है फूट डालो और शासन करो। हमारी नीति सबको साथ लेकर चलने और सबको आगे बढ़ाने की नीति है जबकि टीएमसी की नीति है समाज को बांटना और चुनाव के समय प्रलोभन के जरिये वोटबैंक की राजनीति करना। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने यह तय कर लिया है कि विश्वास किस पर करना है और किस पर नहीं करना है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हम सबको साथ लेकर चलेंगे और उन्हें उनका उचित स्थान और सम्मान देने का भी प्रयास करेंगे।

नागरिकता संशोधन क़ानून पर बोलते हुए श्री नड्डा ने कहा कि नागरिकता संशोधन क़ानून पहले ही संसद से पास हो कर क़ानून बन चुका है। अब इसके नियम बन रहे हैं। इसके तहत पात्रता वाले लोगों को भारत की नागरिकता मिल कर रहेगी। कोरोना के कारण इसमें थोड़ी सी रुकावट आई है लेकिन इस पर जल्द ही काम शुरू होगा। विगत दिनों पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक और पार्टी के कटिबद्ध कार्यकर्ता श्री देवेंद्र नाथ रॉय जी की नृशंस हत्या को निंदनीय करार देते हुए उन्होंने कहा कि देवेंद्र नाथ रॉय जी भी हमारे समाज के प्रतिनिधि थे

लेकिन उनके साथ जो घटना घटी है वह किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। देवेंद्र जी हम सब के दिल में हैं। लोकतंत्र और क़ानून के दायरे में हम इस मामले को निर्णायक मोड़ तक ले जायेंगे, इसका भी विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। जहां तक गोरखा समाज का प्रश्न है, उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है। उनका सशक्तिकरण हमारी जिम्मेवारी है। उनकी मुख्य रूप से दो मांगें हैं - एक तो उनकी समस्या का राजनीतिक समाधान और दूसरा, गोरखा की 11 जनजातियों को मान्यता देना। ये दोनों मुद्दे हमारे संकल्प पत्र में हैं। हम इन दोनों मांगों को पूरा करेंगे। जहां तक यदुवंशी समाज के डेवलपमेंट बोर्ड का प्रश्न है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही इस मांग को भी हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं कि पिछड़ा वर्ग आयोग को भी संवैधानिक मान्यता देने का काम मोदी सरकार ने ही किया है जबकि कांग्रेस की सरकार ने इसे 40 वर्षों से अधिक समय से लटका कर रखा था।

तृणमूल कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में विकास की कई योजनायें तृणमूल सरकार के कारण खटाई में पड़ी हुई है। आज जब चुनाव का समय आया है तो तृणमूल कांग्रेस विभिन्न सामाजिक संगठनों को मुद्दे न उठाने के लिए एक ओर प्रलोभन देती है तो दूसरी ओर डराती-धमकाती है। ये काम वही लोग करते हैं जो जान जाते हैं कि उनकी दमनकारी नीतियों से जनता आक्रोशित है और सत्ता से उन्हें हटाने का मन बना चुकी है। पश्चिम बंगाल में एक ओर तृणमूल कांग्रेस है जो जनता से विश्वासघात करती है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है, कर के दिखाती है, उसे पूरा कर दिखाती है। भारतीय जनता पार्टी समाज को जोड़ती है, टीएमसी समाज को तोड़ती है। हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में यकीन रखते हैं, टीएमसी लोगों को तोड़ कर वोटबैंक की राजनीति करती है।

तृणमूल सरकार पर हमला करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि हिंदू समाज के प्रति ममता सरकार ने कितना गहरा आघात किया है लेकिन जब चुनाव नजदीक आया है तो उन्हें पता चल गया है कि ऐसा करने से नुकसान होगा तो अब वे वोट के लिए हर तरीके से प्रलोभन देने का प्रयास कर रही है। पश्चिम बंगाल की जनता को याद रखना चाहिए कि टीएमसी केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति करती है, सिर्फ सत्ता में बैठने के लिए राजनीति करती है जबकि भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा के लिए राजनीति करती है। यह पश्चिम बंगाल की जनता की जिम्मेवारी है कि वे जनता की सेवा के प्रति समर्पित भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनाएं और हमारी जिम्मेवारी आप सब को साथ लेकर चलने और आपको मुख्यधारा में शामिल करने की है। मैं सभा में आये आप सभी प्रतिनिधियों को धन्यवाद देता हूं। मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों को भी साधुवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे सभी समाज के लोगों की बातों, उनकी मांगों और समस्याओं को सुनने का अवसर दिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी और कंधे से कंधा मिलाकर आपकी समस्याओं का समाधान करेगी। ■

'कार्यालय संगठन कार्य में स्थायित्व देता है'

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 17 अक्टूबर, 2020 को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उत्तराखंड भाजपा प्रदेश कार्यालय के भूमि पूजन एवं शिलान्यास समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यालय अपने कार्यकर्ताओं को महत्व देता है। अगर पार्टी का दफ्तर एक नेता के घर से चलेगा तो पार्टी सिर्फ उस एक व्यक्ति की हो जाती है। कई दल इसके उदाहरण हैं। वहां एक परिवार खुद ही पार्टी बन जाता है, लेकिन भाजपा में पार्टी हमारा परिवार बन जाती है। श्री नड्डा ने कहा कि देश में किसी भी पार्टी का उदाहरण लें। चाहे कांग्रेस हो या कोई अन्य क्षेत्रीय दल वह एक परिवार तक ही सीमित रह गया है। ऐसे दलों में लोग अपने भाइयों, बहनों, माताओं और बेटों को बचाने में व्यस्त हैं। भाई-भतीजों में अंतर्कलह है, लेकिन भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जो एक परिवार की तरह मजबूती से खड़ी है।

उन्होंने कहा कि हम विद्यार्थी काल में कहते थे कि पांच 'क' होने चाहिए। सबसे पहले कार्यकर्ता, फिर उसके साथ कार्यक्रम, सब कुछ चलाने के लिए कोष, उसके बाद कार्यकारणी और इन सबको करने के लिए उत्तम कार्यालय होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण का काम शुरू किया है। अगर कार्यालय काम में स्थायित्व देता है तो प्रशिक्षण विचार में स्थायित्व देता है। इसलिए प्रशिक्षण पर भी हमको पूरा जोर देना पड़ेगा। अभी जो प्रशिक्षण लेंगे, उनका प्रशिक्षण चल रहा है आगे आप सबको उस प्रशिक्षण से जुड़ना पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान सारी पार्टियां लॉक्ड हो गई थी और अभी भी सुषुप्त अवस्था में हैं। लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने लगभग 29 करोड़ फूड पैकेट्स और लगभग 5 करोड़ राशन बांटे, वो भी सिर्फ 3 महीने में। मोदी जी के आह्वान पर भाजपा का एक-एक कार्यकर्ता जनसेवा के लिए निकल पड़ा। ■

गरीब किसानों और ग्रामीणों के हितों को मोदी सरकार ने हमेशा सुनिश्चित किया

कृषि क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनों को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद देने के लिए विशेष समारोह का आयोजन

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 22 अक्टूबर, 2020 को दिल्ली में पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में एक विशेष समारोह को संबोधित किया। कृषि क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनों को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा के अलावा इस आयोजन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के 350 से अधिक गांवों के किसानों और उनके प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

इस अवसर पर श्री नड्डा ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी को हार्दिक बधाई दी और उनको शाल, पगड़ी और हल भेंट करने के लिए केंद्रीय कार्यालय में किसानों और उनके प्रतिनिधियों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, "जिस तरह से आप सभी ने प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिवादन किया और शाल, पगड़ी और हल दिया, वह बहुत प्रशंसनीय है। मैं इन भेंटों को सुरक्षित रखूंगा और व्यक्तिगत रूप से इन्हें प्रधानमंत्री मोदीजी को देने जाऊंगा।"

उन्होंने कहा, "हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में किसानों के हितों की हमेशा रक्षा की जाएगी और नीतियां बनाते वक्त गरीब किसानों और ग्रामीणों के हितों को हमेशा मोदी सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। किसान हमारे अन्नदाता हैं और उन्होंने भारत के सम्मान को हमेशा सुनिश्चित किया है और इसे कभी कमज़ोर नहीं होने दिया है।"

उन्होंने कहा कि भारत में कई बड़े किसान नेता हुए हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी ही एक ऐसे व्यक्तित्व है, जिन्होंने हमारे महान किसानों के जीवन में एक परिवर्तनकारी बदलाव को सुनिश्चित किया है। जिस दिन उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला, मोदीजी ने किसानों के लाभ और उत्थान को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाना शुरू किया। कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम और किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) मूल्य आश्वासन अधिनियम और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम जैसे कृषि कानून हमारे किसानों को सशक्त बनाने में मील का पत्थर साबित होंगे। इससे 'वन नेशन, वन मार्केट' को बढ़ावा मिलेगा।

कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की हालत आज उन लोगों की तरह है जो गली-मोहल्ले में खेले जाने वाले क्रिकेट के खेल में हारने के बाद विकेट उखाड़कर घर वापस चले जाते हैं और फिर कभी नहीं खेलने का दावा करते हैं। कांग्रेस

के नेता चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वे हर बार हार जाते हैं और हारने के बाद हर चीज की आलोचना करने लगते हैं। और यहां तक वह स्वयं (कांग्रेस) की भी आलोचना करते हैं ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है।

श्री नड्डा ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह इस कानून में एमएसपी पर कुछ कहना चाहते हैं। मैं अमरिंदर सिंहजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस तरह के कदम कार्यकारी आदेशों के माध्यम से किए जाते हैं। 55 साल तक केंद्र में आपकी सरकार थी, फिर आपने इसे कानून में क्यों शामिल नहीं किया? आपको किसने रोका था? 2013 में राहुल गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को फलों को एमएसपी से बाहर रखने के लिए कहा था। इतना ही नहीं, 2019 में अपने चुनावी वक्तव्यों में कांग्रेस ने कहा था कि वह अनुबंध खेती को बढ़ावा देगी, मंडियों से संबंधित समस्याओं को दूर करेगी और आवश्यक वस्तु अधिनियम को हटाएगी। कांग्रेस इस बात का केवल ढोल पीटती रही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीजी इस पर आगे बढ़े और किसान हितैषी कानून लाकर किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव को सुनिश्चित किया। राहुल गांधी, क्या आप किसानों के या बिचौलियों के शुभचिंतक हैं जो गरीब किसानों को परेशान करते हैं और धोखा देते हैं या फिर आप सिर्फ उनके चिंतक है जो आपके परिवार को लाभ पहुंचाते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि पंजाब में जो कुछ आपत्तियां उठाई जा रही हैं वह किसानों द्वारा नहीं बल्कि बिचौलियों द्वारा उठाई जा रही है। कांग्रेस को किसानों की नहीं बल्कि बिचौलियों की चिंता है। अगर राहुल गांधी और कैप्टन अमरिंदर सिंह किसानों के शुभचिंतक होते तो वे प्रधानमंत्री मोदीजी को बधाई देते। कांग्रेस ने अपने 10 साल के शासन में महज 54000-55000 करोड़ रुपये के कृषि ऋण माफ किए। उसमें भी भ्रष्टाचार की खबरें सामने आयी और बहुसंख्यक किसानों को इसका लाभ नहीं मिला पाया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठाए, जिसमें प्रत्येक किसान को 6000 रुपये की वार्षिक सहायता देना भी शामिल है ताकि वह खेती करते हुए एक गरिमापूर्ण जीवन जी सके। इस योजना के तहत पूरे भारत में 92000 करोड़ रुपये सीधे किसानों के खाते में जमा किए गए।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठाए, जिसमें प्रत्येक किसान को 6000 रुपये की वार्षिक सहायता देना भी शामिल है ताकि वह खेती करते हुए एक गरिमापूर्ण जीवन जी सके। इस योजना के तहत पूरे भारत में 92000 करोड़ रुपये सीधे किसानों के खाते में जमा किए गए।

उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों को कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने कभी लागू नहीं किया। यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी है, जिन्होंने पूरे भारत के करोड़ों किसानों के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट लागू की। इस क्रांतिकारी कदम के कारण, पहली बार किसानों को उनकी उपज का अधिक मूल्य सुनिश्चित किया गया और एमएसपी को डेढ़ गुना तक बढ़ा दिया गया। 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के तहत आवंटित 20 लाख करोड़ रुपये के फंड में से 1 लाख करोड़ रुपये कृषि बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए आवंटित किए गए हैं। 'वोकल फॉर लोकल' पहल के तहत स्थानीय कृषि उत्पादों की विश्वस्तरीय ब्रांडिंग करने का लक्ष्य भी रखा गया है।।

इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सर्वश्री अरुण कुमार सिंह, दुष्यंत गौतम और तरुण चुघ, भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष श्री राजकुमार चाहर, दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता, दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी उपस्थित थे। भाजपा के लोकसभा सदस्य श्री रमेश बिधूड़ी और श्री प्रवेश वर्मा और किसान प्रतिनिधि श्री नारायण सिंह, श्री अमर सिंह, श्री सिब्बल सिंह सहित बड़ी संख्या में किसान इस आयोजन का हिस्सा बने। ■

आर्थिक विकास तेज करने के लिए 73,000 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 12 अक्टूबर को अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता खर्च को प्रोत्साहित करने के लिए 73,000 करोड़ रुपये के उपायों की घोषणा की। यह घोषणा कोविड-19 महामारी के कारण अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती को दूर करने के प्रयासों के तहत की गई है।

प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा कि ऐसे संकेत मिले हैं कि सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की भी बचत में अच्छी-खासी वृद्धि हुई है और हम विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के लोगों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, ताकि गरीब व्यक्तियों का भी भला हो सके।

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि यदि आज घोषित किए गए प्रोत्साहन उपायों की बदौलत विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग बढ़ती है, तो इसका सकारात्मक प्रभाव उन लोगों या कारोबारियों पर भी पड़ेगा जो कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और जो अपने व्यवसाय को निरंतर जारी रखने के लिए विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग बढ़ने का इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं।

अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) नकद वाउचर योजना

वित्त मंत्री ने इस योजना की घोषणा करते हुए कहा कि एलटीसी नकद वाउचर योजना का लाभ उठाने में कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा प्रोत्साहन यह है कि 2021 में पूरे होने वाले चार साल के ब्लॉक में एलटीसी का लाभ नहीं उठाया गया, तो वो समाप्त हो जाएगी और ये दरअसल कर्मचारियों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। वे इससे वो सामान खरीद सकते हैं, जो उनके परिवार के काम आ सकता है।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 4 साल के ब्लॉक में एलटीसी मिलता है जिसमें वेतनमान/पात्रता के अनुसार हवाई या रेल किराए की प्रतिपूर्ति की जाती है और इसके अलावा 10 दिनों के छुट्टी नकदीकरण (वेतन+डीए) का भुगतान किया जाता है। लेकिन कोविड-19 के कारण कर्मचारी लोग 2018-21 के वर्तमान ब्लॉक में एलटीसी का लाभ उठाने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए सरकार ने 2018-21 के दौरान एलटीसी के बदले नकद भुगतान देने का फैसला किया है, जिसमें शामिल होगाः

- छुट्टी नकदीकरण पर पूर्ण भुगतान
- पात्रता की श्रेणी के आधार पर 3 फ्लैट-दर वाले स्लैब में किराए का भुगतान
- किराया भुगतान कर मुक्त होगा

इस योजना का उपयोग करने वाले कर्मचारी को 31 मार्च, 2021 से पहले किराए के मूल्य का तीन गुना और छुट्टी नकदीकरण के मूल्य का एक गुना सामान/सेवाएं खरीदनी होंगी। यह राशि ऐसे उत्पादों पर खर्च करनी होगी, जिन पर जीएसटी 12 प्रतिशत या अधिक है।

श्रीमती सीतारमण ने कहा कि एलटीसी के लिए सरकार 5,675 करोड़ रुपये खर्च करेगी। वहीं केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा बैंकों को इस सुविधा पर अनुमानित 1,900 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि इस कदम से 19,000 करोड़ रुपये की मांग पैदा होगी। वहीं राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा इस योजना का विकल्प चुनने से 9,000 करोड़ रुपये की मांग और पैदा होगी।

विशेष त्योहार एडवांस योजना

गैर-राजपत्रित कर्मचारियों के साथ-साथ राजपत्रित कर्मचारियों के लिए भी एक विशेष त्योहार एडवांस योजना को मांग को प्रोत्साहित करने के एक मुश्त उपाय के रूप में पुनर्जीवित किया जा रहा है। सभी केन्द्र सरकार के कर्मचारी अपने त्योहार की पसंद के आधार पर 31 मार्च, 2021 तक खर्च की जाने वाली 10,000 रुपये की ब्याज मुक्त एडवांस राशि प्राप्त कर सकते हैं। यह ब्याज मुक्त एडवांस राशि कर्मचारी से अधिक से अधिक 10 किश्तों में वसूलनीय है।

कर्मचारियों को अग्रिम राशि का प्री-लोडेड रुपे कार्ड मिलेगा। सरकार कार्ड के बैंक प्रभारों को वहन करेगी। रुपे कार्ड के माध्यम से अग्रिम राशि का वितरण भुगतान के डिजिटल मोड को सुनिश्चित करता है, जिसके परिणामस्वरूप कर राजस्व और ईमानदार व्यवसायों को प्रोत्साहन मिलेगा।

विशेष त्योहार एडवांस योजना (एसएफएएस) की एक मुश्त वितरण राशि लगभग 4,000 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है। अगर सभी राज्य सरकारें एसएफएएस देती हैं तो 8,000 करोड़ रुपये की अन्य राशि वितरित किए जाने की उम्मीद है। ■

राज्यों को पूंजीगत परियोजनाओं के लिए 12,000 करोड़ रुपये का ब्याज-मुक्त कर्ज देगी केन्द्र सरकार

आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये केन्द्र सरकार राज्यों को 12,000 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त कर्ज उपलब्ध करायेगी। कर्ज 50 साल की अवधि का होगा और यह पूंजीगत परियोजनाओं पर खर्च करने के लिये दिया जायेगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 12 अक्टूबर को इस योजना की घोषणा करते हुये कहा कि 12,000 करोड़ रुपये की राशि में से 1,600 करोड़ रुपये पूर्वोत्तर राज्यों को और 900 करोड़ रुपये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 7,500 करोड़ रुपये की राशि शेष राज्यों को दी जाएगी। वहीं 2,000 करोड़ रुपये उन राज्यों को दिए जाएंगे जिन्होंने पहले बताये गये सुधारों को पूरा कर लिया होगा।

श्रीमती सीतारमण ने योजना के बारे में जानकारी देते हुये कहा कि पूरी राशि नई या मौजूदा पूंजीगत परियोजनाओं पर खर्च की जा सकेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं के लिए बिलों का निपटान भी इससे कर सकते हैं, लेकिन पूरी राशि का भुगतान 31 मार्च, 2021 से पहले करना होगा। उन्होंने कहा कि यह कर्ज राज्यों की उधारी सीमा से अलग होगा। 50 साल बाद राज्यों को इसका भुगतान एक बार में करना होगा।

वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा 25,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त पूंजीगत व्यय की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह अतिरिक्त राशि सड़क, रक्षा ढांचे, जलापूर्ति और शहरी विकास पर खर्च की जाएगी। यह 4.13 लाख करोड़ रुपये के निर्धारित बजट के अतिरिक्त होगी। ■

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू एवं कश्मीर में सेब की खरीद के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के विस्तार को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सत्र 2019-20 में जिस तरह से जम्मू कश्मीर में नियम और शर्तों का पालन किया गया था, उसी तरह वर्तमान सत्र 2020-21 में भी जम्मू एवं कश्मीर में सेब खरीद के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के विस्तार को मंजूरी दे दी।

सेब की खरीद केंद्रीय खरीद एजेंसी यानी राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नैफेड) द्वारा राज्य नामित एजेंसी योजना और विपणन निदेशालय, बागवानी और जम्मू और कश्मीर बागवानी प्रसंस्करण और विपणन निगम के माध्यम से जम्मू एवं कश्मीर के सेब किसानों से सीधे की जाएगी और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। इस योजना के तहत 12 लाख मीट्रिक टन सेब खरीदे जा सकते हैं।

सरकार ने नैफेड को इस अभियान के लिए 2,500 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी उपयोग करने की भी अनुमति दी है। इस अभियान में अगर कोई नुकसान होता है तो उसे 50:50 के आधार पर केंद्र सरकार और जम्मू एवं कश्मीर के केन्द्रशासित प्रदेश प्रशासन के बीच साझा किया जाएगा। ■

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिया 30 लाख से अधिक कर्मचारियों को बोनस

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21 अक्टूबर को साल 2019-2020 के लिए उत्पादकता से जुड़े बोनस भुगतान करने को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी। इससे रेलवे, डाक, रक्षा, ईपीएफओ, ईएसआईसी इत्यादि जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के 16.97 लाख अराजपत्रित कर्मचारी लाभान्वित होंगे और वित्तीय भार 2,791 करोड़ रुपया होगा।

गैर-पीएलबी या एडहॉक बोनस अराजपत्रित केन्द्रीय कर्मचारियों को दिया जाएगा। इससे 13.70 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और जिसका वित्तीय भार 946 करोड़ रुपया होगा। बोनस की घोषणा से कुल 30.67 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और कुल वित्तीय भार 3,737 करोड़ रुपया होगा।

पिछले साल अराजपत्रित कर्मचारियों को उनके प्रदर्शन के लिए बोनस का भुगतान आमतौर पर दुर्गा पूजा/दशहरा से पहले कर दिया जाता था। सरकार अपने अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए उत्पादकता से जुड़े बोनस (पीएलबी) और एडहॉक बोनस के तत्काल भुगतान की घोषणा कर रही है।

कैबिनेट द्वारा कर्मचारियों को बोनस दिए जाने पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया और ट्वीट किया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2019-2020 के लिए उत्पादकता और गैर-उत्पादकता से जुड़े बोनस को मंजूरी देने के लिए आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी का हृदय से धन्यवाद। डीबीटी के माध्यम से 3,737 करोड़ रुपये का बोनस मिलने से 30 लाख कर्मचारी अपने परिवार के साथ त्योहारों पर खुशियां मना सकेंगे। ■

देश के 8 समुद्र तटों को मिला प्रतिष्ठित 'ब्लू फ्लैग' प्रमाणन

भारत के 8 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन 'ब्लू फ्लैग' दिया गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 11 अक्टूबर, 2020 को यह जानकारी दी। प्रमाण पत्र देने का निर्णय एक अंतरराष्ट्रीय निर्णायक समिति ने किया, जिसके प्रतिष्ठित सदस्यों में यूएनईपी, यूएएनडब्ल्यूटीओ, एफईई, आईयूसीएन शामिल थे। 'ब्लू फ्लैग' प्रमाणन एक वैश्विक सम्मान है जो साफ और सुरक्षित समुद्र तटों को दिया जाता है।

'ब्ल्यू फ्लैग' से सम्मानित समुद्र तट हैं- शिवराजपुर (द्वारका-गुजरात), घोघला (दीव), कासरकोड और पादुबिद्री (कर्नाटक), कप्पड़ (केरल), रुशिकोंडा (आंध्र प्रदेश), गोल्डन (पुरी-ओडिशा) और राधा नगर (अंडमान-निकोबार द्वीप समूह)। भारत को तटीय क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए 'अंतरराष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणालियों' के तहत अंतरराष्ट्रीय निर्णायक समिति द्वारा तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इन समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिलने को एक अद्भुत उपलब्धि करार दिया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि भारत के 8 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। यह भारत द्वारा ऐसे स्थानों के संरक्षण और सतत विकास को आगे बढ़ाने के महत्व को दर्शाता है। वास्तव में एक अद्भुत उपलब्धि।

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि यह एक उत्कृष्ट उपलब्धि है। किसी भी देश को पहले ही प्रयास में 8 समुद्र तटों के लिए कभी भी सम्मानित नहीं किया गया है। श्री जावडेकर ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि भारत एशिया-प्रशांत क्षेत्र का पहला देश है जिसने केवल 2 साल के समय में यह उपलब्धि हासिल की है।

जापान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त अरब अमीरात-यूएई एकमात्र अन्य एशियाई राष्ट्र हैं, जिन्हें दो समुद्र तटों के लिये ब्ल्यू फ्लैग से सम्मानित किया गया है और वह भी लगभग 5 से 6 वर्ष में।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत अब 50 'ब्ल्यू फ्लैग' देशों के समूह में शामिल है और हमें अपने राष्ट्र के लिए इस सम्मान पर गर्व है। अगले पांच वर्षों में हम देश में 100 ऐसे समुद्र तटों के लिये ब्ल्यू फ्लैग सम्मान प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं।

भारत ने समुद्र तटों (प्रत्येक तटीय राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में से एक) के विकास के लिए 2018 में अपनी प्रमुख योजना शुरू की थी और आगामी पर्यटन सत्र-2020 के लिए 8 समुद्र तटों के प्रमाणन के साथ पहला सेट प्रस्तुत किया है।

एसआईसीओएम, एमओईएफसीसी, भारत के तटीय क्षेत्रों के 'सतत विकास' की खोज में आईसीज़ेडएम (एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन) परियोजना के तहत एक अत्यधिक प्रशंसित और प्रमुख कार्यक्रम 'बीईएएमएस' (समुद्र तट पर्यावरण और सौंदर्य प्रबंधन सेवाएं) को अपनाया। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित फाउंडेशन ऑफ एनवायरनमेंटल एजुकेशन, एफईई डेनमार्क द्वारा प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय ईको-लेबल 'ब्लू फ्लैग' प्राप्त करने के लिए प्रयास करना था। ■

भारत ने कोविड के कुल 10 करोड़ टेस्ट कराने का लक्ष्य पार किया

भारत ने जनवरी, 2020 से अब तक कोविड-19 के अधिक-से-अधिक टेस्ट कराने के मामले में भारी वृद्धि दर्ज की है। उसने 23 अक्टूबर को कुल 10 करोड़ (10,01,13,085) टेस्ट कराने का लक्ष्य पार कर लिया। एक अन्य उपलब्धि में पिछले 24 घंटों में 14,42,722 टेस्ट कराए गए।

देश में 2000 के करीब प्रयोगशालाएं खोले जाने के बाद हमारी टेस्ट कराने की क्षमता में भारी सुधार हुआ है। इसके अलावा, केन्द्र और राज्य/केन्द्रशासित प्रदेशों के समन्वित प्रयासों से यह संभव हो सका है। अब प्रतिदिन 15 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच का काम किया जा सकता है।

देश के सभी हिस्सों में टेस्ट कराने की अवसंरचना के विस्तार से कराए गए टेस्ट की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। देश में कुल 1989 जांच प्रयोगशालाएं हैं जिनमें से 1122 सरकारी प्रयोगशालाएं और 867 निजी प्रयोगशालाएं हैं।

इनसे सतत आधार पर प्रतिदिन टेस्ट कराने की क्षमता में भारी सुधार आया है और देश में पॉजिटिव मामलों की दर में पर्याप्त गिरावट आई है। इससे यह संकेत मिलता है कि संक्रमण के प्रसार की दर पर प्रभावी तौर से लगाम लगाई जा सकी है। कुल टेस्ट की संख्या के 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाने से समन्वित दर में गिरावट आ रही है। आज पॉजिटिव मामलों की राष्ट्रीय दर 7.75 प्रतिशत हो गई है।

यह केन्द्र सरकार की सफल टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटिंग और टेक्नोलॉजी की रणनीति का और राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों द्वारा इसे प्रभावी तौर पर लागू किए जाने का नतीजा है।

विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर की जा रही टेस्टिंग से पॉजिटिव मामलों की तत्काल पहचान करने में सफलता मिली है। इसके अलावा, प्रभावी निगरानी और ट्रेसिंग के जरिए मामलों की जल्द शिनाख्त और अस्पतालों और घरों एवं चिकित्सा केन्द्रों में गंभीर मामलों का समय पर तथा प्रभावी उपचार किया जा सका है। इससे मृत्यु दर में धीरे-धीरे गिरावट आने लगी है। ■

राष्ट्र की सुरक्षा के प्रश्न को सर्वोपरि महत्त्व दिया जाए

| दीनदयाल उपाध्याय |

बाह्य आक्रमण अथवा अन्य कोई आंतरिक संकट किसी भी राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए संकट का कारण बन सकता है। इसी प्रकार यदि कोई देश आंतरिक दृष्टि से जर्जर हुआ तो वह शीघ्र ही बाह्य आक्रमणों का शिकार बन बैठता है। लेकिन बाह्य आक्रमण के फलस्वरूप कई बार राष्ट्र में राष्ट्रीय एकता की उग्र भावना भी उत्पन्न हुई है और इसलिए उसे संकट के समय का वरदान भी कहा जाता है। अंग्रेजी की एक कहावत के अनुसार ऐसे राष्ट्र के विषय में यह कहा गया है कि वह युद्धकाल में तो जीवित रहता है, पर शांति का समय उसके लिए मृत्यु का द्वार है। फिर भी, इस तर्क के आधार पर कोई युद्ध की कल्पना अथवा योजना नहीं कर सकता। लेकिन प्रत्येक राष्ट्र को आत्मरक्षार्थ सैनिक एवं मानसिक दृष्टि से सदैव सिद्ध रहना आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना कोई भी राष्ट्र संसार में अपनी स्वतंत्रता को अधिक दिन तक टिकाकर नहीं रख सकता। इतना ही नहीं, एक राष्ट्र को बाह्य आक्रमणों से आत्मरक्षा करने की तैयारी के अतिरिक्त देश में विद्यमान विघटन एवं पृथकतावादी तत्वों का सामना करने के लिए भी तत्पर रहना चाहिए। पर यदि देश में कोई ऐसा राजनीतिक दल है, जो राष्ट्र की एकता और अखंडता की ओर से उदासीन है तो उसके द्वारा न विघटनवादी तत्त्वों का सामना करना ही संभव है और न ही वह शत्रु का प्रतिकार कर सकता है। वास्तव में ऐसा दल, जो राष्ट्रीय सुरक्षा की ओर से इस प्रकार उदासीन हो तो वह राष्ट्र के अस्तित्व को बनाए रखने में भी सफल नहीं हो सकता।

जनसंघ का कथन अनसुना किया गया

जब कम्युनिस्ट चीन द्वारा भारत के विस्तृत भू-भाग पर अनुचित क़ब्ज़ा किए जाने की बात प्रकाश में नहीं आई थी, जनसंघ को छोड़कर देश का प्रत्येक राजनीतिक दल राष्ट्र की सुरक्षा की ओर से उदासीन था और पाकिस्तान द्वारा दी जानेवाली धमकियों को ये दल सांप्रदायिक मस्तिष्क का प्रलाप कहकर शांत हो जाते थे अथवा पाकिस्तान को अपनी सरकार द्वारा विरोध-पत्र भेजने को पर्याप्त समझ उसके प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाए जाने के समर्थक थे। इन राजनीतिक दलों ने चीन की ओर से भी कभी संकट उपस्थित हो सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं की थी और पंचशील

के भावोन्मेष में वे इस ओर से पूरी तरह से उदासीन थे।

चीन की यह वकालत

यही कारण है कि सन् 1957 के चुनावों के समय प्र.स. और समाजवादी दलों ने जहां अपने घोषणा-पत्रों में तिब्बत पर चीन के क़ब्ज़े और दक्षिण-पूर्वी एशिया में उसके बढ़ते प्रभाव पर चुप्पी साध रखी थी, वहां कांग्रेस ने भारत-चीन की मित्रता का राग अलाप कर देश का बहुत बड़ा अहित किया था। सन् 1957 के कांग्रेस चुनाव घोषणापत्र में कहा गया था कि 'पिछले कई वर्षों में चीन ने एक जनवादी गणतंत्र प्रस्थापित कर अपने को एक सबल राष्ट्र के रूप में खड़ा कर लिया है, जो निरंतर प्रगति करता जा रहा है। भारत और चीन के राजनीतिक और आर्थिक ढांचे में पर्याप्त भिन्नता होने के बाद भी चीन भारत का एक महान् पड़ोसी मित्र राष्ट्र है। चीन को राष्ट्र संघ में स्थान दिलाने के लिए भारत सदैव प्रयत्न भी करता रहा है, परंतु हमें दुःख है कि संसार के अनेक राष्ट्रों ने इसका विरोध किया है। लेकिन विश्व के एक चौथाई जनसंख्या वाले इस देश को जब तक राष्ट्र संघ में स्थान नहीं दिया जाता, वह वास्तविक अर्थों में न तो पूर्ण प्रतिनिधित्व वाला एक विश्व-संगठन बन सकता है और न ही सुदूर पूर्व अथवा दक्षिण-पूर्वी एशिया की समस्याएं ही चीन के सहयोग के बिना हल की जा सकती है।'

क्या यह देशद्रोह नहीं?

पर जब यह घोषणा-पत्र तैयार किया गया था, उस समय तक चीन ने लद्दाख के क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाकर भारतीय क्षेत्र के अंदर अपनी एक सड़क भी बना ली थी। भारत सरकार पेकिंग को इस संबंध में विरोध-पत्र भी प्रेषित कर चुकी थी, लेकिन भारतीय जनता को इसकी सूचना नहीं दी गई, यहां के कांग्रेसी नेता यह सब जानते थे। कम-से-कम पंडित नेहरू, जिन्होंने कांग्रेस का उक्त घोषणा-पत्र तैयार किया भलीभांति परिचित ही थे। ऐसी स्थिति में शत्रु को चेतावनी न देकर और भारतीय जनता का आह्वान न करते हुए कांग्रेस का घोषणा-पत्र चीन की महानता और उसकी प्रगति का चिट्ठा देश के सम्मुख रख रहा था, जिसके लिए देशद्रोही की संज्ञा दी की जा सकती है।

हमने चेतावनी दी थी

इन सब दलों से भिन्न भारतीय जनसंघ ही उस समय एकमात्र ऐसा दल था, जो चीन की ओर से सशंकित था और जिसने पाकिस्तान की शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का उल्लेख करने के पश्चात् सन् 1951 के अपने चुनाव घोषणा-पत्र में लिखा था कि भारत का उत्तरी सीमांत भी सुरक्षित नहीं है। भारत के शांतिपूर्ण दृष्टिकोण

की उपेक्षा करते हुए चीन ने तिब्बत की स्वाधीनता नष्ट कर उसे गुलाम बना लिया है, जो सह-अस्तित्व की नीति के विरुद्ध है। नेपाल से संधि करते समय भी चीन ने वहां पर भारत की विशेष स्थिति को ध्यान में नहीं रखा है। इसी भांति चीन नक्शों पर भारतीय क्षेत्र को दिखाना, जिसे ग़लती से दिखाया गया बताया गया था, वहां चीनी सेनाओं के प्रवेश (जिसका कारण ग़लतफ़हमी बताया गया था) और दक्षिण पूर्वी एशिया के छोटे-छोटे देशों में चीनियों की जो गतिविधियां चल रही हैं, उनकी ओर से भारत को सतर्क रहना चाहिए। 'इससे स्पष्ट है कि जनसंघ ने चीनियों को समझने में उस समय भी कोई ग़लती नहीं की थी।'

काश! सरकार पहले चेतती तो...

सन् 1957 में जनसंघ को छोड़कर अन्यान्य राजनीतिक दल देश की सुरक्षा को आर से उदासीन थे और राजनीतिक और आर्थिक कार्यक्रमों को ही वे महत्त्व दे रहे थे। लेकिन जनसंघ ने उस समय सुरक्षा के प्रश्न को सर्वोपरि महत्त्व का प्रश्न बताया था और उसके लिए अपने सुझाव देते हुए उसने कहा था कि देश की सेनाओं को बढ़ाने, विकसित करने, उनमें राष्ट्रीय भावनाएं उत्पन्न करने के साथ ही उन्हें आधुनिकतम शस्त्रों से सुसज्जित करना चाहिए। युवकों के लिए अनिवार्य सैनिक शिक्षा दिए जाने का भी हमने सुझाव दिया था। यह जानते हुए कि अपने अल्प साधनों के द्वारा राज्य-सरकारें सीमांत क्षेत्र की उचित सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर सकतीं, केंद्र के अधीन एक सीमांत पुलिस एस्टैब्लिशमेंट स्थापित करने का सुझाव भी जनसंघ ने दिया था। यदि सीमांत-निरीक्षण एवं सुरक्षा का यह कार्य केंद्र ने पहले से ही अपने हाथ में लिया होता तो अक्साइ चिन में चीनियों के घुसने के समाचार का ज्ञान सरकार को काफी दिनों पूर्व ही हो जाता।

आज जब कि हमारी सीमाएं असुरक्षित हैं और आक्रमण जारी है, तब राष्ट्र की सुरक्षा के प्रश्न पर कोई भी मौन नहीं रह सकता। पर यह दुःख की बात है कि विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस प्रश्न को अपने चुनाव घोषणा-पत्रों में अधिक महत्त्व नहीं दिया है।

चीन के आक्रमण के प्रश्न पर कम्युनिस्ट चुप्पी क्यों साधे हुए हैं?

तीन प्रमुख बातें

राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टि से हमें तीन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है- अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने के साथ हम यह भी देखें कि यहां पंचमांगी तत्त्व न रहने पाएं और न कोई अनधिकृत व्यक्ति उक्त क्षेत्र में प्रवेश कर सके। दूसरे हमें अपने भूभाग को मुक्त कराना चाहिए और तीसरे देश की रक्षा-व्यवस्था में वृद्धि कर सेना की सभी असुविधाओं का हल शीघ्रातिशीघ्र ढूंढ़ निकालना चाहिए।

देश की सेनाओं को बढ़ाने, विकसित करने, उनमें राष्ट्रीय भावनाएं उत्पन्न करने के साथ ही उन्हें आधुनिकतम शस्त्रों से सुसज्जित करना चाहिए।

जनसंघ के सुझाव

सीमांत सुरक्षा और घुसपैठ को रोकने के लिए भी जनसंघ को छोड़कर किसी भी दल ने अपने सुझाव नहीं दिए हैं। जनसंघ का कहना है-

केंद्र को सीमांत क्षेत्र की रक्षा के लिए एक विशेष पुलिस दल प्रस्थापित करने के साथ ही तस्कर व्यापार रोकने और अनुचित घुसपैठ को रोकने का भी प्रबंध करना चाहिए। भारत के गुप्तचर विभाग का आधुनिकीकरण करते हुए विदेशी गुप्तचरों और पंचमांगियों की कार्रवाइयों को उनकी हरकतें बढ़ने से पहले ही रोकने का उपाय करना चाहिए। इसी भांति जनसंघ का मत है कि असम और कश्मीर में अनधिकृत रूप से आए पाकिस्तानियों को तुरंत देश के बाहर निकाल देना चाहिए।

सीमांत-क्षेत्र के विकास के लिए विशेष प्रयत्न

सीमांत क्षेत्र विकास पर बल देते हुए जनसंघ ने अपने घोषणा-पत्र में कहा है कि 'सीमांत क्षेत्र के विकास के लिए विशेष प्रयत्न किए जाएंगे। इस दृष्टि से योजना बनाकर उन्हें आवश्यक धन प्रदान किया जाएगा और जहां आवश्यक होगा उनका कार्यान्वयन सुरक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा। यातायात के साधनों का विकास करने के साथ इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास की भी आवश्यक व्यवस्था की जाएगी। प्रजा समाजवादी दल ने भी इसी भांति सीमांत क्षेत्र में विशेष प्रयत्न करने की बात को दुहराया है।

जहां तक विदेशी चंगुल में पड़े भारतीय भूभाग को मुक्त कराने का प्रश्न के दल उसको आवश्यक बताते हैं। किंतु आक्रमण समाप्त करने के लिए बताए गए उपायों में परस्पर बहुत अधिक भिन्नता है और इसका कारण प्रत्येक दल की विदेश-नीति और संसार के शक्तिगुटों की ओर देखने का उनका दृष्टिकोण है।

चीन व पाक के कारनामे

पाकिस्तान और चीन इस समय भारत के भूभाग को दबाए हुए बैठे हैं। युद्धविराम रेखा समझौते के कारण कश्मीर का एक-तिहाई भूभाग पाकिस्तान के क़ब्ज़े में है। चीन ने भारतीय भूभाग के विशाल क्षेत्र पर अपना दावा उपस्थित कर उसके कुछ अंश को हस्तगत कर लिया है और सभी समझौतों को तोड़ते हुए वह अपनी ज़िद पर अड़ा है। भारत सरकार ने भी उक्त क्षेत्र को मुक्त करने की दृष्टि से कोई भी पग नहीं उठाया है। जहां तक पाकिस्तान का संबंध है, उसने युद्ध विराम रेखा का बड़े पैमाने पर उल्लंघन नहीं किया है। यद्यपि समय-समय पर पाकिस्तानी उक्त रेखा को पारकर भारतीय ग्रामों में लूटमार करते रहते हैं और पाकिस्तान 'जेहाद' की धमकियां देता रहता है। पूर्वी सीमा पर भी तुकेरग्राम और पथरिया जंगल के क्षेत्र में फायरिंग आदि की घटनाएं हई हैं और पाकिस्तान ने अपना अनुचित अधिकार वहां पर बना रखा है। किंतु चीन भारत को बराबर धमकियां देने के साथ आगे भी बढ़ता जाता है और भारतीय विरोध-पत्रों को उसने कभी भी मान्य नहीं किया है। ■

क्रमशः

-पाञ्चजन्य, जनवरी ११, १९६२, संघ शिक्षा वर्ग, बौद्धिक वर्ग : लखनऊ

'राजनीति के अजातशत्रु'—कैलाशपति मिश्र

(5 अक्टूबर 1923 - 3 नवंबर 2012)

भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक श्री कैलाशपति मिश्र को बिहार भाजपा का 'भीष्म पितामह' कहा जाता है। श्री मिश्र का जन्म बक्सर जिले में दुधारचक गांव में 5 अक्तूबर, 1923 को हुआ था। 1942 के 'अंग्रेजो भारत छोड़ो' आंदोलन में वे 10वीं के छात्र रहते हुए जेल गए। 1945 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सम्पर्क में आए, तो फिर अपने राष्ट्र और समाज की सेवा ही उनका ध्येय बन गया।

संघ प्रचारक के रूप में श्री मिश्र ने आरा से सामाजिक जीवन प्रारंभ किया, 1947 से 52 तक पटना में प्रचारक रहे, 1952 से 57 तक पूर्णिया के जिला प्रचारक रहे, फिर संघ के निर्देश पर ही जनसंघ में गए। 1959 में जनसंघ के प्रदेश संगठन मंत्री का दायित्व मिला, तो आपातकाल के बाद चुनावी राजनीति में उतरने के निर्देश का भी पालन किया। विक्रम विधानसभा से चुनाव लड़े, जीते और कर्पूरी ठाकुर की सरकार में वित्त मंत्री भी रहे।

1980 में भारतीय जनता पार्टी की बिहार इकाई के वे पहले प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत हुए, फिर 1983 से 1987 तक निर्वाचित अध्यक्ष रहे। इस बीच श्री मिश्र 1984 से 1990 तक राज्यसभा के भी सदस्य रहे। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के साथ ही अनेक राज्यों के संगठन मंत्री का दायित्व भी उन्होंने बखूबी निभाया। 7 मई, 2003 से 7 जुलाई, 2004 तक वे गुजरात के राज्यपाल पद पर भी आसीन रहे। इसी दौरान 4 माह के लिए राजस्थान के राज्यपाल का कार्यभार भी उन पर था।

50 वर्ष से अधिक लम्बी चली उनकी राजनीतिक जीवन की यात्रा में न उन पर कोई आरोप लगा और न ही वे किसी विवाद का अंग बने। राजनीति की दलदल में कमल के समान अहंकार, बुराई, द्वेष, लोभ-लालच आदि सामान्य दोषों से भी अछूते रहने वाले श्री कैलाशपति मिश्र अपनी इन्हीं विशिष्टताओं के कारण भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं के लिए आज भी आदर्श एवं प्रेरणास्रोत हैं।

श्री कैलाशपति मिश्र एक साहित्यकार भी थे। इनकी लिखी पुस्तकों में 'पथ के संस्मरण' (आत्मकथा) और 'चेतना के स्वर' (कविता संग्रह) प्रमुख हैं। इनकी मृत्यु 3 नवंबर 2012 को पटना में हुई। ■

भाजपा नेता व बिहार सरकार में मंत्री विनोद कुमार सिंह नहीं रहे

वरिष्ठ भाजपा नेता व बिहार सरकार में पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री श्री विनोद कुमार सिंह का 12 अक्टूबर को निधन हो गया। वे 54 वर्ष के थे। श्री सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की थी।

2000 में प्राणपुर विधान सभा क्षेत्र से वे पहली बार विधायक चुने गए। श्री सिंह 2010 व 2015 में पुनः विधायक निर्वाचित हुए। उन्हें नीतीश मंत्रिमंडल में खान एवं भूतत्व मंत्री बनाया गया। इसके बाद उन्हें पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री की जिम्मेवारी सौंपी गई।

शोक संदेश

श्री विनोद कुमार सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट किया कि बिहार के पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री विनोद कुमार सिंह जी के निधन से अत्यंत दुःख पहुंचा है। वे गरीबों-वंचितों के सशक्तिकरण के लिए समर्पित रहे। उन्होंने राज्य में भाजपा को मजबूत बनाने में भी अहम भूमिका निभाई। उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति!

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने श्री सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया और ट्वीट कर कहा कि बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार में मंत्री श्री विनोद कुमार सिंह के निधन की दुःखद सूचना प्राप्त हुई। जनता की सेवा और संगठन के प्रति उनका समर्पण सदैव याद किया जायेगा। उनका निधन भाजपा के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं।

बिहार सरकार में उपमुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी ने श्री सिंह के असामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने श्री सिंह के परिजनों के प्रति आत्मिक संवेदना व्यक्त करते हुए उनके शुभचिंतकों, समर्थकों को दुःख की इस घड़ी में धैर्य व दिवंगत की आत्मा को शांति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। ■

जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 20 अक्टूबर को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में देश की कोविड महामारी के खिलाफ चल रही लड़ाई में सभी नागरिकों से ढिलाई न बरतने और आत्मसंतोष से बचने की विनम्र अपील की। श्री मोदी ने कहा कि भले ही लॉकडाउन हटा दिया गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोरोना वायरस का देश से सफाया हो गया है।

प्रधानमंत्री ने अमेरिका और यूरोप की वर्तमान स्थिति का उल्लेख किया, जहां कोरोना के मामलों की संख्या शुरू में कम हुई लेकिन फिर अब अचानक से बढ़ने लगी है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे तब तक कोई भी ढिलाई न बरतें, जब तक कि महामारी के खिलाफ वैक्सीन या दवाई न मिल जाए और जब तक कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई सफल न हो जाये।

मानवता को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास जारी

श्री मोदी ने कहा कि मानवता को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास जारी हैं और भारतीय वैज्ञानिकों सहित अनेक देश वैक्सीन के उत्पादन पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ विभिन्न टीकों पर काम चल रहा है और इनमें से कुछ एक उन्नत चरण में हैं।

श्री मोदी ने कहा कि सरकार हर एक नागरिक तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए एक विस्तृत रोड मैप भी तैयार कर रही है, जो कि वैक्सीन को आसानी से उपलब्ध करा सके। उन्होंने लोगों से फिर आग्रह किया कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है, तब तक वे ढिलाई न बरतें।

प्रधानमंत्री ने पूरे देश में स्थिति में हो रहे सुधार की सराहना की और आर्थिक गतिविधि सामान्य होने पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने इस बात की भी सराहना की कि लोगों ने जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अपने घरों से बाहर निकलना शुरू कर दिया है।

श्री मोदी ने कहा कि त्योहारों के आगमन के साथ बाजार भी सामान्य स्थिति में लौटने लगे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 7-8 महीनों में हर भारतीय के प्रयासों के कारण भारत बेहतर स्थिति में है और किसी को भी इसे बिगड़ने नहीं देना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में रोगियों के स्वस्थ होने की दर में सुधार हुआ है और मृत्यु दर कम हो रही है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर लगभग 5,500 लोग ही कोरोना से संक्रमित हुए थे, जबकि अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर यह आंकड़ा लगभग 25,000 है।

उन्होंने कहा कि भारत में प्रति 10 लाख की आबादी पर मृत्यु की दर 83 है, जबकि विकसित राष्ट्रों जैसे अमेरिका, ब्राजील, स्पेन और ब्रिटेन सहित कई अन्य देशों में यह संख्या लगभग 600 है। प्रधानमंत्री ने सराहना की कि कई विकसित देशों की तुलना में भारत में ज्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा रही है।

कोविड अवसंरचना में उल्लेखनीय सुधार

श्री मोदी ने देश में कोविड अवसंरचना में सुधार का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अब देश में 90 लाख से अधिक बिस्तर, 12 हजार क्वारंटीन केंद्र उपलब्ध हैं। श्री मोदी ने कहा कि 2000 से अधिक कोरोना जांच प्रयोगशालाएं पूरे देश में कार्य कर रही हैं, जबकि परीक्षणों की संख्या जल्द ही 10 करोड़ को पार कर जाएगी।

भारत विश्व के संसाधन समृद्ध देशों की तुलना में अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों की जान बचाने में सफल हो रहा है।

उन्होंने कहा कि भारत विश्व के संसाधन समृद्ध देशों की तुलना में अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों की जान बचाने में सफल हो रहा है। जांच की बढ़ती संख्या कोविड महामारी से लड़ाई में एक प्रमुख ताकत रही है। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर, नर्स और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि, वे सब 'सेवा परमो धर्मः' के मंत्र पर चलते हुए विशाल जनसमुदाय की निःस्वार्थ सेवा कर रहे हैं।

श्री मोदी ने लोगों को चेतावनी दी कि इन सभी प्रयासों के बीच अभी आप यह न मानें कि कोरोना वायरस चला गया है, या अब कोरोना से कोई खतरा नहीं है। ऐसे लोगों को सावधान करते हुए, जिन्होंने सावधानी बरतना बंद कर दिया है, उन्होंने कहा कि यदि आप लापरवाही कर रहे हैं और बिना मास्क के बाहर जा रहे हैं, तो आप अपने आप को, अपने परिवार, अपने बच्चों और बुजुर्गों को उतनी ही मात्रा में जोखिम में डाल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान में हम एक कठिन समय से गुजर रहे हैं और थोड़ी सी लापरवाही एक बड़े संकट का कारण बन सकती है और यह हमारी खुशी को धूमिल कर सकती है। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि वे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए सतर्क रहें। ■

प्रधानमंत्री ने एफएओ की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 75 रुपये का सिक्का जारी किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एफएओ की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 16 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। इस अवसर पर उन्होंने हाल ही में विकसित की गई फसलों की 17 किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने दुनिया भर में कुपोषण को खत्म करने के लिए निरंतर काम कर रहे लोगों को बधाई दी।

उन्होंने कहा कि कुपोषण खत्म करने के लिए हमारे किसान साथी, हमारे अन्नदाता और कृषि वैज्ञानिक तथा आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता इस आंदोलन के आधार हैं। इन लोगों ने न सिर्फ भारत का अन्न भंडार भरा है, बल्कि सरकार के गरीब से गरीब लोगों तक पहुंचने के प्रयास में मददगार सिद्ध हो रहे हैं।

श्री मोदी ने कहा कि इनके प्रयासों के चलते ही कोरोना वायरस संकट के दौर में भी भारत कुपोषण के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ पा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते वर्षों में एफएओ ने भारत सहित दुनियाभर में कृषि उत्पादन बढ़ाने और भुखमरी समाप्त करने के लिए मददगार की भूमिका अदा की है और पोषण बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसे 130 करोड़ से अधिक भारतीय सम्मान देते हैं।

उन्होंने कहा कि इस साल विश्व खाद्य कार्यक्रम को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना भी एफएओ के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री मोदी ने कहा कि भारत इस संस्थान के साथ ऐतिहासिक साझेदारी को लेकर प्रसन्नता का अनुभव करता है।

एफएओ ने विश्व खाद्य कार्यक्रम का आरंभ डॉ. बिनय रंजन सेन के नेतृत्व में शुरू किया था। उन्होंने महिलाओं और भूखमरी का सामना करने वाले लोगों की समस्याओं को बेहद नजदीकी से देखा था और उनके द्वारा किए गए कार्य समूचे विश्व के लिए आज भी उपयोगी हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि एफएओ ने विश्व खाद्य कार्यक्रम का आरंभ डॉ. बिनय रंजन सेन के नेतृत्व में शुरू किया था। उन्होंने महिलाओं और भूखमरी का सामना करने वाले लोगों की समस्याओं को बेहद नजदीकी से देखा था और उनके द्वारा किए गए कार्य समूचे विश्व के लिए आज भी उपयोगी हैं।

श्री मोदी ने कहा कि एफ़एओ ने भारत में दशकों चली कुपोषण की लड़ाई को नजदीकी से देखा है। हालांकि इसमें अभी भी कई विसंगतियां बरकरार हैं। उन्होंने कहा कि कम उम्र में गर्भवती बनने, शिक्षा की कमी, सूचनाओं की कमी, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, स्वच्छता का अभाव इत्यादि ऐसे कारण हैं जिनके चलते हमें अपेक्षित परिणाम अभी तक नहीं मिले हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्षों के अनुभवों के बाद देश में 2014 के उपरांत नए प्रकार के प्रयास किए गए। श्री मोदी ने कहा कि सरकार के समेकित और एकीकृत प्रयासों के चलते बहुआयामी रणनीतिक कदम उठाए गए।

उन्होंने कुपोषण को खत्म करने के लिए सरकार की कुछ कार्य प्रणालियों का जिक्र किया जिसमें राष्ट्रीय पोषण मिशन (पोषण अभियान), स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय का निर्माण, मिशन इंद्रधनुष, जल जीवन मिशन और सस्ती दर पर सैनिटेशन पैड उपलब्ध कराना इत्यादि शामिल हैं।

इन प्रयासों के उपरांत निकले परिणामों का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने लड़कियों के नामांकन दर का उल्लेख किया, जो लड़कों की तुलना में बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि कुपोषण को खत्म करने के लिए प्रोटीन, आयरन, जिंक इत्यादि पोषक तत्वों से समृद्ध खाद्यान्न अनाजों को प्रोत्साहित किया गया।

प्रधानमंत्री ने वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा दिवस घोषित करने के भारत को प्रस्ताव को पूर्ण समर्थन देने के लिए एफएओ को धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि इससे पोषण युक्त खाद्य पदार्थों के इस्तेमाल में वृद्धि होगी और इसकी उपलब्धता बढ़ाने को लेकर छोटे किसानों को लाभ पहुंचेगा।

उन्होंने कहा कि गेहूं और धान समेत अनेक स्थानीय और पारंपरिक फसलों की 17 बायोफोर्टीफाइड किस्मों के बीज आज से किसानों के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ■

प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के वितरण का किया शुभारंभ

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 11 अक्टूबर को स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया और योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। श्री मोदी ने स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को शुभकामनाएं दीं, जिन्होंने आज अपने घरों के संपत्ति कार्ड प्राप्त किए हैं और कहा कि अब लाभार्थियों के पास अपने घरों के मालिक होने का एक कानूनी दस्तावेज होगा। यह योजना देश के गांवों में ऐतिहासिक बदलाव लाने जा रही है।

उन्होंने कहा कि देश ने एक अति महत्वाकांक्षी भारत की ओर एक और बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि इस योजना से ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। श्री मोदी ने कहा कि हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के एक लाख लाभार्थियों को आज उनके घरों के कानूनी कागजात सौंप दिए गए हैं और अगले तीन-चार वर्षों में देश के प्रत्येक गांव में हर परिवार को ऐसे संपत्ति कार्ड देने का वादा किया।

प्रधानमंत्री ने दो महान नेताओं जय प्रकाश नारायण और नाना जी देशमुख की जयंती पर संपत्ति कार्ड वितरित करते हुए खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इन दोनों महापुरुषों की जयंती न सिर्फ एक ही तिथि पर पड़ती है, बल्कि उनके संघर्ष और आदर्श भी समान थे। उन्होंने बताया कि ग्रामीण भारत और गरीबों के सशक्तिकरण के लिए नानाजी और जेपी दोनों ने आजीवन संघर्ष किया।

नानाजी के शब्द 'जब तक गांव के लोग विवादों में उलझे रहेंगे, तो न तो वे खुद को विकसित कर पाएंगे और न ही समाज को' को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनका मानना है कि हमारे गांवों में कई विवादों को समाप्त करने के लिए स्वामित्व एक बड़ा माध्यम बन जाएगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के विकास में भूमि और घर का स्वामित्व एक बड़ी भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि जब संपत्ति का रिकॉर्ड होता है तो नागरिक आत्मविश्वास हासिल करते हैं और निवेश के नए रास्ते खुलते हैं। संपत्ति, रोजगार और स्व-रोजगार के रिकॉर्ड पर बैंक से ऋण आसानी से उपलब्ध होता है। लेकिन मुश्किल यह है कि आज दुनिया में केवल एक-तिहाई जनसंख्या के पास कानूनी रूप से अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड है।

श्री मोदी ने कहा कि संपत्ति कार्ड ग्रामीणों के लिए किसी भी विवाद के बिना संपत्ति खरीदने और बेचने का रास्ता साफ करेगा। उन्होंने कहा कि आज हमारे पास गांव में बहुत सारे युवा हैं जो अपने दम पर कुछ करना चाहते हैं। संपत्ति कार्ड प्राप्त करने के बाद उनके घरों पर बैंकों से ऋण की आसान पहुंच सुनिश्चित की जाएगी।

संपत्ति कार्ड ग्रामीणों के लिए किसी भी विवाद के बिना संपत्ति खरीदने और बेचने का रास्ता साफ करेगा। आज हमारे पास गांव में बहुत सारे युवा हैं जो अपने दम पर कुछ करना चाहते हैं। संपत्ति कार्ड प्राप्त करने के बाद उनके घरों पर बैंकों से ऋण की आसान पहुंच सुनिश्चित की जाएगी।

उन्होंने कहा कि मैपिंग और सर्वेक्षण में ड्रोन का उपयोग करने जैसी नई तकनीक से हर गांव के लिए सटीक भूमि रिकॉर्ड बनाए जा सकते हैं। सटीक भूमि रिकॉर्ड के बल पर गांव में विकास संबंधी कार्य भी आसान हो जाएंगे, जो इन संपत्ति कार्डों का एक और लाभ होगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामित्व योजना पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करने में मदद करेगी, जिसके लिए पिछले 6 वर्षों से प्रयास चल रहे हैं। उन्होंने पिछले 6 वर्षों में ग्राम पंचायतों को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा की और कहा कि स्वामित्व योजना नगर पालिकाओं और नगर निगमों की तरह व्यवस्थित तरीके से हमारे ग्राम पंचायतों के लिए ग्राम प्रबंधन को आसान बनाएगी।

श्री मोदी ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में गांवों में पुरानी कमियों को दूर करने के लिए लगातार प्रयास किए गए। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों में गांवों में अभूतपूर्व स्तर पर विकास हुआ है, जो कि स्वतंत्रता मिलने के बाद पिछले सात दशकों में नहीं हुआ।

उन्होंने पिछले 6 वर्षों में बैंक खाता, बिजली कनेक्शन, शौचालय तक पहुंच, गैस कनेक्शन प्राप्त करना, एक पक्का घर होना और पाइप पेयजल कनेक्शन होना आदि जैसे ग्रामीणों को मिलने वाले लाभों के बारे में चर्चा की। श्री मोदी ने कहा कि देश के हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन से जोड़ने का एक बड़ा अभियान भी तेज गति से चल रहा है। ■

'सड़कें और पुल किसी भी राष्ट्र की जीवन-रेखा हैं'

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीआरओ निर्मित 44 पुलों को राष्ट्र को समर्पित किया

पश्चिमी, उत्तरी और उत्तर-पूर्वी सीमाओं के करीब संवेदनशील क्षेत्रों में सड़कों और पुलों की कनेक्टिविटी में एक नए युग में शुरुआत करते हुए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 12 अक्टूबर को 44 प्रमुख स्थायी पुलों को राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में नेचिपु सुरंग के लिए आधारशिला भी रखी। ये पुल रणनीतिक महत्व के हैं और दूरदराज के क्षेत्रों को कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। ये 44 पुल सात राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में फैले हुए हैं।

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ जनरल बिपिन रावत, चीफ ऑफ आर्मी स्टॉफ जनरल एम.एम. नरवाना और रक्षा सचिव श्री अजय कुमार की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समर्पण समारोह नई दिल्ली में आयोजित किया गया।

अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने महानिदेशक और सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के सभी रैंकों को उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई दी और कहा कि एक ही बार में 44 पुलों का समर्पण एक रिकॉर्ड है। श्री सिंह ने कहा कि कोविड-19 के चुनौतीपूर्ण समय में और पाकिस्तान और चीन द्वारा सीमा तनाव और विवादों के बावजूद देश न केवल उनका सामना कर रहा है, बल्कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकास के सभी क्षेत्रों में ऐतिहासिक बदलाव ला रहा है।

सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका के लिए बीआरओ की सराहना करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि इन पुलों ने पश्चिमी, उत्तरी और उत्तर-पूर्व क्षेत्रों के दूर-दराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार किया और स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया। उन्होंने कहा कि इनसे पूरे वर्ष सशस्त्र बलों के परिवहन और रसद संबंधी आवश्यकताएं भी पूरी होंगी।

उन्होंने कहा कि सड़कें और पुल किसी भी राष्ट्र की जीवन-रेखा हैं और सुदूरवर्ती क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि सभी परियोजनाओं की प्रगति की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है और उनके समय पर निष्पादन के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जा रहा है।

श्री सिंह ने कहा कि बीआरओ का वार्षिक बजट वर्ष 2008-2016 के बीच 3,300 करोड़ रुपये से बढ़कर 4,600 करोड़ रुपये हो गया। इतना ही नहीं, 2020-21 में यह धनराशि 11,000 करोड़ रुपये से भी अधिक हो गई। कोविड-19 के बावजूद इस बजट में कोई कमी नहीं की गई। रक्षा मंत्री ने यह भी घोषणा की कि सरकार ने बीआरओ के इंजीनियरों और श्रमिकों को उच्च ऊंचाई वाले कपड़े के प्रावधान किए हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप ये पुल सुदूर सीमा क्षेत्रों के समग्र आर्थिक विकास में योगदान करेंगे और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सशस्त्र बलों की शीघ्र तैनाती में भी सहायता करेंगे।

श्री सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग की सड़क पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नेचिपु सुरंग की आधारशिला भी रखी। यह 450 मीटर लंबी, दो लेनों वाली सुरंग सभी मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगी और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में एक सुरक्षित मार्ग प्रदान करेगी।

बीआरओ के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने गणमान्य व्यक्तियों संबांधित करते हुए कहा कि 30 मीटर से लेकर 484 मीटर तक के विभिन्न आकार के 44 पुल जम्मू-कश्मीर (10), लद्दाख (08), हिमाचल प्रदेश (02), पंजाब (04), उत्तराखंड (08), अरुणाचल प्रदेश (08) और सिक्किम (04) में स्थित हैं। वे सामरिक महत्व के हैं और सीमा क्षेत्रों में नागरिक और सैन्य यातायात की भारी आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप ये पुल सुदूर सीमा क्षेत्रों के समग्र आर्थिक विकास में योगदान करेंगे और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सशस्त्र बलों की शीघ्र तैनाती में भी सहायता करेंगे।

बीआरओ ने रणनीतिक महत्व के कार्यों जैसे कि प्रमुख पुल और सड़क, अटल सुरंग रोहतांग, सेला सुरंग आदि के निर्माण और सामरिक पर्वतीय मार्ग के उद्घाटन के लिए स्नो क्लीयरेंस के साथ कोविड-19 महामारी संबंधी प्रतिबंधों के दौरान भी लगातार काम किया है। ■

देश की खातिर अब तक 35,398 पुलिसकर्मियों ने न्योछावर किए अपने प्राणः अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर 21 अक्टूबर को नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री शाह ने कहा कि देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता और सार्वभौमिकता की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात सशस्त्र बलों के जवानों और देशभर के सभी पुलिसकर्मियों के सर्वोच्च बलिदान के लिए समग्र देश की ओर से कृतज्ञतापूर्वक नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मंत्रिपरिषद की ओर से भी शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धासुमन अर्पित किए।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 2014 में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक ऐसे स्मारक का निर्माण करने का फैसला लिया, जो देश के लोगों को पुलिसकर्मियों के बलिदान की याद दिलाता रहे। 21 अक्टूबर, 2018 को प्रधानमंत्री ने यह स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया। राष्ट्रीय पुलिस स्मारक का निर्माण जनता, विशेषकर आने वाली पीढ़ी का पुलिस बल के प्रति नजरिया बदलने का मोदी सरकार का एक सार्थक और गंभीर प्रयास है।

श्री शाह ने कहा कि मैं शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों से कहना चाहता हूं कि पुलिस स्मारक पर शहीदों के नाम ही अंकित नहीं हैं, बल्कि 130 करोड़ भारतीय के मन की भावना भी अंकित है। यह स्मारक सिर्फ पत्थर, ईंट, चूने और सीमेंट से बना स्मारक नहीं है, यह स्मारक हमें हमेशा याद दिलाता है कि इन वीर जवानों ने देश की आजादी को अमरत्व देने का काम किया है।

राष्ट्रीय पुलिस स्मारक सिर्फ पत्थर, ईंट, चूने और सीमेंट से बना स्मारक नहीं है, यह स्मारक हमें हमेशा याद दिलाता है कि इन वीर जवानों ने देश की आजादी को अमरत्व देने का काम किया है।

गृह मंत्री ने कहा कि उनके खून का एक-एक कतरा देश को विकास के पथ पर आगे ले गया है, कई नौनिहालों के भविष्य को संवारा है और देश के आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया है। श्री अमित शाह ने यह भी कहा कि अमर शहीदों के सर्वोच्च बलिदान के कारण ही देश चैन की नींद सोता है।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) और पुलिस के 264 कर्मी शहीद हुए और अब तक 35,398 जांबाज पुलिसकर्मियों ने देश की खातिर अपने प्राण न्योछावर किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पुलिसकर्मियों को 24 घंटे और 365 दिन तैनात रहकर अपना काम करना पड़ता है और तीज-त्यौहार पर भी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रहते हैं।

श्री शाह ने कहा कि जब कोरोना की महामारी आई उस वक्त पूरी

दुनिया अचंभित हो गई थी कि उसका कैसे सामना किया जाए। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इससे निपटने के लिए लॉकडाउन का आह्वान किया तो पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश के गृह मंत्री के नाते मुझे यह कहते हुए बहुत गर्व होता है कि लॉकडाउन को प्रभावी ढंग से लागू करने में पुलिसबलों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही।

गृह मंत्री ने कहा कि आज पुलिस के सामने बहुत चुनौतियां हैं और उनका काम कई डाइमेंशन में बढ़ा है। पुलिस के सामने आतंकवाद, फेक करेंसी, नारकोटिक्स कंट्रोल, शस्त्रों की तस्करी, मानव तस्करी, साइबर क्राइम और महिलाओं के विरुद्ध अपराध जैसे बहुत सारी नई चुनौतियां आ रही हैं। जिसके लिए भारत सरकार ने एक सुगठित पुलिस मॉडर्नाइजेशन का प्रोग्राम शुरू किया है।

श्री शाह ने कहा कि दुनिया की अपेक्षा भारत में प्रति एक लाख व्यक्ति पर पुलिसबल की संख्या कम है, मगर मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में कई योजनाओं पर काम चल रहा है।

उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में संसद सत्र के दौरान रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी और फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी संबन्धित दो विधेयक पारित किए गए। रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी से छात्रों को इस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने में मदद मिलेगी। इसी तरह फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के माध्यम से वैज्ञानिकों की कमी पूरी करने का प्रयास किया जाएगा।

पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्तूबर, 1959 में लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में भारी हथियारों से लैस चीनी सेना द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में शहीद हुए दस पुलिसकर्मियों की याद में मनाया जाता है। ■

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आंध्र प्रदेश में 16 एनएच परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया

केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा एमएसएमई मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 16 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में 15,592 करोड़ रुपये की लागत वाली 1411 किलोमीटर लंबी 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि मई 2014 से पहले आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 4193 किलोमीटर थी, जो अब बढ़कर 6860 किलोमीटर हो गई है। अतः राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई में बीते 6 वर्षों में 2667 (64%) किलोमीटर का इज़ाफ़ा हुआ है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 34,100 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण का कार्य डीपीआर के स्तर पर है, जिसके अंतर्गत काम 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य है। 25,440 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण क्रियान्वयन के चरण में है। उन्होंने कहा कि 18,100 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाओं में 50-60 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है।

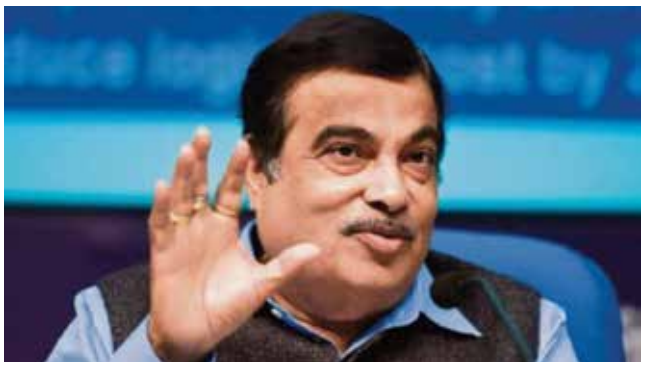

प्रधानमंत्री के नए भारत की परिकल्पना के लिए भारत के सबसे बड़े बुनियादी ढांचा विकास कार्यक्रम भारतमाला परियोजना के अंतर्गत विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे को विकसित करने पर प्राथमिकता से काम किया जा रहा है।

कंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य में 5000 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण भारतमाला परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है। इसके साथ ही भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बंदरगाहों को जोड़ने के लिए 400 किलोमीटर लंबी सड़कों का भी निर्माण किया जाएगा। देश में मौजूद राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क में 35,000 किलोमीटर लंबी सड़क को भारतमाला परियोजना के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारतमाला परियोजना के अंतर्गत दिल्ली-मुंबई-एक्सप्रेसवे, दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे, चेन्नई-बंगलुरु एक्सप्रेसवे, अनंतपुर-अमरावती एक्सप्रेसवे आदि को विकसित किया जा रहा है।

श्री गडकरी ने बताया कि 335 किमी लंबे अनंतपुर-अमरावती एक्सप्रेसवे का निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से आंध्र प्रदेश के राजधानी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्रों में सड़क संपर्क-मार्ग बेहतर होगा और यह क्षेत्र में आर्थिक संपन्नता सुनिश्चित करने में अहम भूमिका अदा करेगा।

उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे के लिए 16 पैकेज हैं और इसके लिए 20,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है। एक्सैस कंट्रोल वाला यह एक्सप्रेसवे आंध्र प्रदेश के नए राजधानी शहर अमरावती को रायलसीमा क्षेत्र के अनंतपुरम से जोड़ेगा, जिससे आंध्र प्रदेश राज्य की जीवन रेखा माने जाने वाले एनएच-44 और एनएच-16 के बीच बेहतर संपर्क-मार्ग उपलब्ध होगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बंगलौर-चेन्नई एक्सप्रेसवे भी भारतमाला परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है, जिसकी लंबाई 262 किलोमीटर है। एक्सैस कंट्रोल वाला यह एक्सप्रेसवे बंगलौर और चेन्नई के बीच बेहतर संपर्क-मार्ग सुनिश्चित करेगा और क्षेत्र में आर्थिक संपन्नता में बड़ी भूमिका अदा करेगा। इसके 85 किलोमीटर लंबे क्षेत्र का विकास आंध्र प्रदेश में 5,200 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि इसके अलावा 7,585 करोड़ रुपये के निवेश से 878 किलोमीटर की 16 अन्य परियोजनाओं का आवंटन किया जा चुका है, जिन पर काम शुरू हो गया है। इसमें विजयवाड़ा में वेस्टर्न साइड बेंज़ सर्कल फ्लाईओवर का निर्माण भी शामिल है। 8,306 करोड़ रुपये की लागत से 637 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजनाओं के 2020-21 में पूर्ण होने की संभावना है। इसमें 3850 करोड़ रुपये की लागत वाली 150 किलोमीटर की 8 परियोजनाएं एनएचएआई द्वारा, जबकि 4456 करोड़ रुपये की लागत से 487 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजनाएं 'सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय' द्वारा निर्मित की जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि इसके अलावा 11,712 करोड़ रुपये की लागत से 535 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना पर काम का आवंटन चालू वित्त वर्ष में किया जाना है। इसमें 9071 करोड़ रुपये की लागत वाली 217 किलोमीटर की 4 परियोजनाएं एनएचएआई के अधीन, जबकि 2641 करोड़ रुपये की 318 किलोमीटर लंबी 9 सड़क परियोजनाएं 'सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय' के अधीन निर्मित होंगी। ■

राजमाता विजया राजे सिंधिया के सम्मान में 100 रुपये का विशेष स्मारक सिक्का जारी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 12 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजमाता विजया राजे सिंधिया के जन्मशती समारोह के समापन के उपलक्ष्य में 100 रुपये के मूल्य का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया। उन्होंने राजमाता को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि वह बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें राजमाता विजया राजे सिंधिया जी के सम्मान में 100 रुपये के मूल्य का विशेष स्मारक सिक्का जारी करने का अवसर मिला है। श्री मोदी ने विजया राजे जी की पुस्तक का उल्लेख करते हुए कहा कि इस पुस्तक में उन्हें गुजरात के युवा नेता के रूप में प्रस्तुत किया गया था और आज इतने वर्षों के बाद वह देश के प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि राजमाता विजया राजे सिंधिया उन लोगों में से एक थीं जिन्होंने देश को सही दिशा में आगे बढ़ाया। वे एक निर्णायक नेता और कुशल प्रशासक भी थीं। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने भारतीय राजनीति के सभी महत्वपूर्ण चरण देखे हैंः चाहे वो विदेशी कपड़ों की होली जलाना हो, आपातकाल हो या राम मंदिर आंदोलन हो।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा पीढ़ी के लिए राजमाता के जीवन के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि राजमाता और उनके अनुभवों के बारे में बार-बार उल्लेख किया जाए।

श्री मोदी ने कहा कि राजमाता ने हमें जन सेवा के बारे में सिखाया है और बताया है कि इसके लिए किसी विशेष परिवार में जन्म लेना जरूरी नहीं है। इसके लिए राष्ट्र प्रेम और लोकतांत्रिक स्वभाव की जरूरत है। इन विचारों और आदर्शों को उनके जीवन में देखा जा सकता है। राजमाता के पास हजारों कर्मचारी थे, एक शानदार महल था और सभी सुविधाएं उपलब्ध थीं, लेकिन उन्होंने अपना जीवन आम लोगों के लिए और गरीबों की आकांक्षाओं के प्रति समर्पित कर दिया था। वो हमेशा जन सेवा से जुड़ी रहीं और उसके प्रति ही प्रतिबद्ध रहीं।

उन्होंने कहा कि राजमाता ने अपने आपको राष्ट्र के भविष्य के लिए समर्पित कर दिया था। राजमाता ने देश की भावी पीढ़ियों के लिए अपनी सारी खुशियां न्योछावर कर दी थीं। राजमाता पद और प्रतिष्ठा के लिए नहीं जीती थीं और न ही उन्होंने कोई राजनीति की।

प्रधानमंत्री ने ऐसे कुछ अवसरों का स्मरण किया जब राजमाता ने कई पदों को बड़ी विनम्रता से ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा कि एक बार अटल जी और आडवाणी जी ने राजमाता से जनसंघ का अध्यक्ष बनने का अनुरोध किया था, लेकिन उन्होंने एक कार्यकर्ता के रूप में ही जनसंघ की सेवा करना स्वीकार किया था।

राजमाता विजया राजे सिंधिया उन लोगों में से एक थीं जिन्होंने देश को सही दिशा में आगे बढ़ाया। वे एक निर्णायक नेता और कुशल प्रशासक भी थीं।

श्री मोदी ने कहा कि राजमाता अपने साथियों को नाम से पहचानना पसंद करती थीं। एक कार्यकर्ता के प्रति ऐसी भावना हर मनुष्य के मन में होनी चाहिए। गर्व के बजाय सम्मान राजनीति का मूल होना चाहिए। उन्होंने राजमाता को एक आध्यात्मिक शख्सियत बताया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जन जागरूकता और जन आंदोलनों के कारण पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश में कई बदलाव हुए हैं और अनेक अभियान व योजनाएं भी सफल हुई हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि राजमाता के आशीर्वाद से आज देश विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है।

श्री मोदी ने कहा कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में आज नारी शक्ति आगे बढ़ रही। उन्होंने सरकार की उन पहलों को सूचीबद्ध किया जिनसे राजमाता के महिला सशक्तिकरण के सपनों को पूरा करने में मदद मिली है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भी एक अद्भुत संयोग है कि जिस रामजन्मभूमि मंदिर का उन्होंने सपना देखा और जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया, वह सपना उनके जन्म शताब्दी के वर्ष में पूरा हुआ है। उन्होंने कहा कि 'आत्मनिर्भर भारत' की सफलता एक मजबूत, सुरक्षित और समृद्ध भारत के उनके विजन को साकार करने में हमारी मदद करेगा। ■

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 5,718 करोड़ रुपये की परियोजना 'स्टार्स' को दी मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 14 अक्टूबर को निम्नलिखित की मंजूरी दी:

- विश्व बैंक से 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 3700 करोड़ रुपये) राशि की विश्व बैंक की सहायता से 5718 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत वाली 'स्ट्रेंगथनिंग टीचिंग-लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स (एसटीएआरएस)' का कार्यान्वयन।
- स्टार्स परियोजना स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय (एमओई) के तहत एक नई केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में लागू की जाएगी।
- राष्ट्रीय आकलन केन्द्र, परख की स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वतंत्र एवं स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में स्थापना और सहायता करना।

इस परियोजना में 6 राज्य– हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और ओडिशा शामिल हैं। इन पहचान किए राज्यों को शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के विभिन्न उपायों के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। इस परियोजना के अतिरिक्त 5 राज्यों- गुजरात, तमिलनाडु, उत्तराखंड, झारखंड और असम में इसी प्रकार की एडीबी वित्त पोषित परियोजना लागू करने की भी कल्पना की गई है। सभी राज्य अपने अनुभव और श्रेष्ठ प्रक्रियाएं साझा करने के लिए एक दूसरे राज्य के साथ भागीदारी करेंगे।

स्टार्स परियोजना बेहतर श्रम बाजार परिणामों के लिए बेहतर शिक्षा परिणामों और स्कूलों द्वारा पारगमन रणनीतियों के साथ काम करने के लिए प्रत्यक्ष जुड़ाव के साथ उपायों को विकसित करने, लागू करने, आकलन करने और सुधार करने में राज्यों की मदद चाहती है। स्टार्स परियोजना का समग्र फोकस और इसके घटक गुणवत्ता आधारित शिक्षण परिणामों की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के उद्देश्यों के साथ पंक्तिबद्ध है।

इस परियोजना में चुनिंदा राज्यों में हस्तक्षेपों के माध्यम से भारतीय स्कूली शिक्षा प्रणाली में समग्र निगरानी और मापक गतिविधियों में सुधार लाने की कल्पना की गई है। यह परियोजना इन परिणामों के साथ निधियों की प्राप्ति और वितरण को जोड़कर वास्तविक परिणामों के साथ इनपुट और आउटपुट के रखरखाव के प्रावधान से ध्यान केन्द्रित करने में बदलाव करती है।

स्टार्स परियोजना के प्रमुख घटक है

राष्ट्रीय स्तर पर इस परियोजना में निम्नलिखित उपायों की कल्पना की गई है, जिनसे सभी राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश लाभान्वित होंगे:

- छात्रों के प्रतिधारण, संक्रमण और समापन दरों के बारे में मजबूत और प्रामाणिक डेटा प्राप्त करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की राष्ट्रीय डेटा प्रणालियों को मजबूत बनाना।
- राज्य प्रोत्साहन अनुदान (एसआईजी) के माध्यम से राज्यों के शासन सुधार एजेंडा को प्रोत्साहन देकर राज्यों के पीजीआई अंकों में सुधार लाने में शिक्षा मंत्रालय की मदद करना।
- शिक्षण मूल्यांकन प्रणालियों को मजबूत बनाने में सहायता करना।
- राष्ट्रीय आकलन केन्द्र (परख) स्थापित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के प्रयासों में मदद करना। ऐसे केन्द्र के कार्यों में ऑनलाइन पोर्टलों (उदाहरण के लिए शगुन और दीक्षा), सोशल एवं अन्य मीडिया, तकनीकी कार्यशालाओं, राज्य भ्रमणों और सम्मेलनों के माध्यम से अन्य राज्यों के साथ इन अनुभवों के संग्रहित, क्यूरेटिंग और साझा करके संचालन हेतु चुनिंदा राज्यों के अनुभव से लाभ उठाना शामिल है।

इसके अलावा, स्टार्स परियोजना में राष्ट्रीय घटक के तहत आकस्मिकता, आपातकालीन प्रतिक्रिया घटक (सीईआरसी) शामिल हैं जो इसे किसी प्राकृतिक, मानव निर्मित और स्वास्थ्य आपदाओं के लिए अधिक जवाबदेह बनाएंगे। ये स्कूल बंदी/बुनियादी ढांचा हानि, अपर्याप्त सुविधाएं और रिमोट लर्निंग में सहायता प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग जैसी शिक्षण हानि को बढ़ावा देने वाली स्थितियों से निपटने में सरकार की मदद करेंगे। सीईआरसी घटक वित्त पोषण के त्वरित पुनः वर्गीकरण और सहज वित्तीय अनुरोध प्रकियाओं के उपयोग में मदद करेगा।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में पीएम ई-विद्या, आधारभूत साक्षरता एवं न्यूमरैसी मिशन तथा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम एवं शुरुआती बाल देखभाल तथा शिक्षा के लिए कार्यक्रम जैसी पहलों पर जोर देना भी स्टार्स परियोजना का लक्ष्य है।

राज्य स्तर पर परियोजना में निम्नलिखित परिकल्पनाएं की गई हैं:

- शुरुआती बाल शिक्षा एवं आधारभूत शिक्षण को सशक्त बनाना
- शिक्षण आकलन प्रणालियों में सुधार लाना
- शिक्षक के विकास और स्कूल के नेतृत्व के माध्यम से क्लास रूम के निर्देश एवं सुधार को सशक्त करना
- उन्नत सेवा आपूर्ति के लिए शासन एवं विकेंद्रित प्रबंधन
- स्कूल से वंचित बच्चों को मुख्यधारा में लाकर, कैरियर मार्गदर्शन तथा परामर्श देकर, इंटर्नशिप देकर स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा को सशक्त बनाना।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में पीएम ई-विद्या, आधारभूत साक्षरता एवं न्यूमरैसी मिशन तथा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम एवं शुरुआती बाल देखभाल तथा शिक्षा के लिए कार्यक्रम जैसी पहलों पर जोर देना भी स्टार्स परियोजना का लक्ष्य है। ■

कृषि सुधार विधेयकों से किसानों को क्रांतिकारी बदलावों की उम्मीद

राजकुमार चाहर

सन 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही श्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों की भलाई के लिए अनेक कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सबसे पहले किसानों को होने वाली यूरिया की किल्लत को दूर करने के लिए उसे नीम कोटेड कराना अनिवार्य कर दिया। इससे यूरिया की कृषि कार्यों से इतर उपयोग के लिए होने वाली तस्करी और कालाबाजारी पर रोक लग गई और किसानों को नियमित रूप से पूरे देश में यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित हो गई।

इसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कई योजनाएं शुरू कीं। जिसमें डॉ. स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार किसानों को उनकी लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी देने की घोषणा की गई। इसके अलावा पूरे देश में स्वॉयल टेस्टिंग का एक बड़ा कार्यक्रम चलाया गया और भूमि के स्वास्थ्य की जानकारी का रिकॉर्ड तैयार कराया गया। मोदी सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की और हर किसान को 6000 रुपया सालाना उसके बैंक खाते में भेजना सुनिश्चित कराया।

इस साल कोरोना महामारी के कारण किसानों की आय प्रभावित न हो इसके लिए भी सरकार ने कई कदम उठाए। किसानों को लॉकडॉउन के कई प्रतिबंधों से राहत दी गई। इन सभी उपायों के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव लाने के लिए तीन कृषि सुधार विधेयक पेश किए और उन्हें संसद से पारित करा कर कानून बना दिया। इन तीनों कानूनों-कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) विधेयक 2020, कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक-2020 का असर भविष्य में बहुत दूरगामी होने जा रहा है।

कृषि विधेयकों के पारित होते ही विपक्ष ने किसानों को गुमराह करने के लिए कई प्रयास किए। लेकिन किसान अब तक की सभी सरकारों की नीतियों को देखते हुए विपक्ष के बहकावे में आने के लिए तैयार नहीं हुए।

पहले किसान अपनी फसल को केवल कुछ बिचौलियों के माध्यम से ही बेच सकते थे। लेकिन अब वह अपनी फसल कभी भी और कहीं भी बेच सकते हैं इसके अलावा वे किसी से भी अपनी फसल का अग्रिम करार कर सकते हैं।

जैसे ही हरियाणा और पंजाब में एमएसपी पर धान की खरीद शुरू हो गई, विपक्ष का यह थोथा दावा खत्म हो गया कि इन तीनों कानूनों के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य को समाप्त कर देगी। जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पिछले साल की तुलना में ज्यादा खरीद मोदी सरकार कर रही है। कोरोना के तमाम लॉकडाउन नियमों के बावजूद सरकारी एजेंसियों ने पिछले रबी सीजन में 389.85 लाख टन गेहूं की खरीद किसानों से एमएसपी पर की है, जो कि एक रिकॉर्ड है। इसी तरह धान की खरीद में 2014-15 की तुलना में 2019-20 में करीब 80 फ़ीसद की बढ़ोतरी देखी गई।

विपक्ष के तमाम दावों को प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ध्वस्त करते हुए कहा कि जो लोग किसानों को सही लाभकारी मूल्य देने में विफल रहे हैं, वे अब अफवाहें फैला रहे हैं। तीनों कृषि सुधार विधेयकों के माध्यम से सबसे ज्यादा लाभ छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा। आजादी के बाद कई दशक तक किसानों के नाम पर खूब नारेबाजी की गई, लेकिन उनको कुछ खास लाभ नहीं दिया गया और निहित स्वार्थी तत्व उसके लिए अफवाह फैला रहे हैं।

नए कृषि सुधार विधायकों से सबसे ज्यादा लाभ उन भारतीय किसानों को होगा जो दूरदराज और पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। नए कृषि अधिनियम किसान समुदाय के लिए एक नई क्रांतिकारी शुरुआत है। पहले किसान अपनी फसल को केवल कुछ बिचौलियों के माध्यम से ही बेच सकते थे। लेकिन अब वह अपनी फसल कभी भी और कहीं भी बेच सकते हैं। इसके अलावा वे किसी से भी अपनी फसल का अग्रिम करार कर सकते हैं।

पहले सरकारी एजेंसियां किसानों से उपज खरीद लेती थीं लेकिन उसकी कीमत भुगतान में काफी विलंब होता था। किसानों को पता नहीं होता था कि उनकी कीमतों का भुगतान कब किया जाएगा। लेकिन मोदी सरकार ने जो कृषि विधेयक लागू किए हैं उसमें किसानों को उनकी उपज के तत्काल भुगतान की गारंटी दी गई है। इसके लिए साफ कहा गया है कि केवल विशेष परिस्थितियों में ही अधिकतम 3 दिन का विलंब करने की अनुमति है, वरना किसानों को उनकी फसल का भुगतान तत्काल सुनिश्चित करने की गारंटी सरकार दे रही है।

अभी तक किसान मंडियों में अपनी फसल औने-पौने भाव में बेच रहे थे, लेकिन

अब उन्हें मंडी के बाहर भी कहीं भी देश भर में अपनी फसल बेचने की आजादी होगी। विपक्ष बेकार में किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है जिसमें वह कभी सफल नहीं होगा। वैसे भी मंडियों में कहीं-कहीं पर बहुत ज्यादा टैक्स लगता है। जैसे पंजाब में विभिन्न फसलों पर मंडियों में अधिकतम 8.5 फीसद तक का टैक्स लगाया गया है, जो किसानों पर बहुत भारी पड़ता है। इसके अलावा मंडी तक उन्हें अपनी फसल लाने में भी किराया चुकाना होता है।

अगर किसान किसी से फसल का करार कर ले या अगर उसके घर के पास ही कोई खरीदार मिल जाए तो उसे इन सब चीजों से उसे छुटकारा मिल जाएगा। किसान मंडी परिसर के बाहर, भीतर या अपने घर पर अपनी फसल को बेच सकता है। इसका निर्धारण वह अपने लिए ज्यादा दाम के आधार पर करेगा। छोटे किसानों को सरकारी एमएसपी का लाभ नहीं मिल पाता है। क्योंकि देश में 86% किसान छोटी जोत के हैं। इसलिए अब उनको इन कानूनों का फायदा मिलेगा और वह भी अपनी फसल कहीं भी बेच सकेंगे।

कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट केवल फसल का होगा, खेत का नहीं। इसलिए विपक्ष जो यह अफवाह फैला रहा है कि किसानों के खेत बड़ी कंपनियां हड़प लेंगी, इसका कोई आधार नहीं है। किसान अपने खेत का मालिक था, है और रहेगा। अगर किसान और किसी कंपनी के बीच फसल के मूल्य को लेकर करार होता है और फसल तैयार होने के समय फसल का मूल्य बढ़ जाता है तो इसका लाभ भी किसान को मिलेगा।

निहित स्वार्थी तत्व अपने राजनीतिक लाभ के लिए कृषि सुधार विधेयकों पर किसानों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। इन सभी का उद्देश्य इसको चुनावी मुद्दा बनाना है। सबसे बड़ी बात यह है कि कृषि सुधार विधेयकों को लेकर उन चीजों के बारे में अफवाह फैलाई जा रही है जो कि उस विधेयक में हैं ही नहीं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) की 75वीं वर्षगांठ पर एक विशेष स्मारक सिक्का जारी करते हुए कहा कि कोरोना में जब पूरी दुनिया संकट से जूझ रही थी तब भारत के किसानों ने अपनी मेहनत और लगन से कृषि पैदावार के सारे पिछले रिकार्डों को तोड़ दिया है और उनका सहयोग करने के लिए सरकार ने भी एमएसपी पर सरकारी खरीद के सारे पिछले रिकार्ड को तोड़ दिया है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने साफ कर दिया कि एमएसपी पर सरकारी खरीद देश की खाद्य सुरक्षा का अहम हिस्सा है, इसके लिए इसका जारी रहना बहुत स्वाभाविक चीज है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार द्वारा उठाए गए इन सभी कदमों का असर भी दिखाई दे रहा है। न केवल कृषि उत्पादन बढ़ा है, बल्कि जब कोरोना के काल में सभी औद्योगिक उत्पादों का निर्यात घट रहा था तो कृषि वस्तुओं का निर्यात करीब 43.4 प्रतिशत बढ़ा है।

इसे हमेशा जारी रखा जाएगा, किसानों को इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए बहुत गंभीरता से कई कोशिशें कर रही है। इसके लिए कई विशेष किसान रेलों का संचालन शुरू किया गया है। पहली किसान रेल देवलाली (नासिक-महाराष्ट्र) से दानापुर (पटना-बिहार) के लिए चलाई गई। इस ट्रेन की लोकप्रियता में बहुत वृद्धि होने के बाद इसे मुजफ्फरपुर तक बढ़ा दिया गया और इसका संचालन भी सप्ताह में दो बार किया जा रहा है। इसके अलावा सांगली और पुणे से इसमें लिंक कोच भी शुरू कर दिए हैं जो किसान रेल से मनमाड में जोड़े जाते हैं। दूसरी किसान रेल अनंतपुर (आंध्र प्रदेश) से आदर्श नगर (दिल्ली) तक चलती है। यह साप्ताहिक ट्रेन है। तीसरी किसान रेल बेंगलुरु से हजरत निजामुद्दीन के बीच चलाई जा रही है।

इन किसान रेलगाड़ियों के माध्यम से किसान अपनी फसलों को देश में कहीं भी भेज सकते हैं। अब इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी की सरकार ने किसानों को इन विशेष ट्रेनों में माल भाड़े में 50 प्रतिशत सब्सिडी देने का निर्णय किया है। यह सब्सिडी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ऑपरेशन ग्रीन्स 'टॉप टू टोटल योजना' के तहत सीधे किसानों को प्रदान करेगा। इसके लिए रेल मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के बीच एक समझौता भी हुआ है और यह सब्सिडी 14 अक्टूबर से लागू हो गई है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार द्वारा उठाए गए इन सभी कदमों का असर भी दिखाई दे रहा है। न केवल कृषि उत्पादन बढ़ा है, बल्कि जब कोरोना के काल में सभी औद्योगिक उत्पादों का निर्यात घट रहा था तो कृषि वस्तुओं का निर्यात करीब 43.4 प्रतिशत बढ़ा है। अप्रैल-सितंबर 2020 के दौरान कृषि वस्तुओं का निर्यात 43.4 प्रतिशत बढ़ा है। जिसमें मूंगफली, चीनी गेहूं, बासमती चावल और गैर बासमती चावल का निर्यात सबसे ज्यादा बढ़ा है।

सरकार ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि निर्यात नीति-2018 की घोषणा की थी। इस योजना में नकदी फसलों जैसे-फलों, सब्जियों और मसालों की निर्यात केंद्रित खेती पर जोर दिया जाता है। इसके लिए विशेष कृषि समूहों का गठन करने की कोशिश की जाती है और इन विशिष्ट निर्यात उत्पादों को प्रोत्साहित किया जाता है। मोदी सरकार ने कृषि निर्यातकों के लिए संपूर्ण उत्पादन श्रृंखला आधारित कई कार्यक्रम शुरू किए हैं और 8 निर्यात संवर्धन मंच (इपीएफ) स्थापित किए हैं, जिसका नतीजा अब सामने आया है। ■

(लेखक भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद हैं)

चालू वित्त वर्ष के पांच महीनों में ईपीएफओ लाभार्थियों की संख्या में 20 लाख की वृद्धि

ईपीएफओ द्वारा 20 अक्टूबर, 2020 को प्रकाशित आरंभिक पेरोल आंकड़ों से पता चलता है कि चालू वित्त वर्ष के शुरुआती पांच महीनों के दौरान ईपीएफओ लाभार्थियों की संख्या में लगभग 20 लाख की वृद्धि हुई है। कोविड-19 महामारी के चलते देश भर में लागू लॉकडाउन के कारण चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान नामांकन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। हालांकि, जुलाई और अगस्त, 2020 के लिए आरंभिक पेरोल आंकड़े कोविड-19 महामारी के नकारात्मक प्रभाव को कम करता हुआ दिखाई देते हैं और पूर्व-कोविड स्तर पर पहुंचने के संकेत देते हैं। जुलाई, 2020 के दौरान लगभग 7.49 लाख नए लाभार्थी जोड़े गए जो पिछले वर्ष के इसी महीने यानी जुलाई, 2019 के दौरान जुड़े लाभार्थियों की कुल संख्या का लगभग 64% है। अगस्त, 2020 में वृद्धि के इस रुझान में और सुधार हुआ, आंकड़े इसका प्रमाण हैं। इस साल अगस्त महीने में अगस्त, 2019 में दर्ज सदस्यता की तुलना में लगभग 93% लाभार्थी जुड़े। ईपीएफओ की सदस्य संख्या में वृद्धि के संबंध में इसे सामान्य स्थिति की तरफ पहुंचने का संकेतक के तौर पर माना जा सकता है।

नए सदस्यों के जुड़ने के मामले में जुलाई, 2020 की तुलना में अगस्त, 2020 में 34% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। अगस्त, 2020 के महीने में सदस्य संख्या में इस वृद्धि का आधार अधिक से अधिक संख्या में नए लाभार्थियों का जुड़ना और पुराने सदस्यों का संगठन न छोड़ना है। जुलाई, 2020 में जहां 6.48 लाख नए सदस्य ईपीएफओ से जुड़े, वहीं अगस्त, 2020 में 6.70 लाख लाभार्थी जुड़े। इसके अलावा, ईपीएफओ से बाहर जाने वाले सदस्यों की संख्या के मामले में जुलाई की तुलना में अगस्त में 50% की कमी। जुलाई, 2020 में जहां 5.08 लाख सदस्यों ने ईपीएफओ छोड़ा वहीं अगस्त में यह संख्या घटकर 2.46 लाख हो गई। ईपीएफओ से अलग होने वाले लगभग 5.81 लाख सदस्यों ने अगस्त, 2020 में फिर से सदस्यता ली। इन सदस्यों ने ईपीएफओ द्वारा कवर किए जाने वाली कंपनियों में नौकरी बदलने के बाद अपनी सदस्यता को बरकरार रखा, बजाए सदस्यता छोड़ने और जमा राशि निकालने के। प्रकाशित किए गए आंकड़ों में उन सभी नए सदस्यों को भी शामिल किया गया है जो महीने के दौरान शामिल हुए हैं और जिनका योगदान प्राप्त हो चुका है। ■

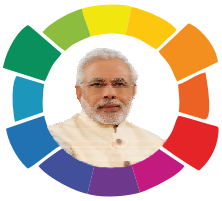

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बने

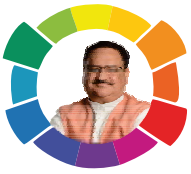

आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चेक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चेक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एफएओ की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजमाता विजया राजे सिंधिया के जन्मशती के उपलक्ष्य में
100 रुपये का विशेष स्मारक सिक्का जारी करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कमल संदेश

अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध

लॉग इन करें:

www.kamalsandesh.org

राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

@Kamal.Sandesh

@KamalSandesh

kamal.sandesh

KamalSandeshLive

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित
आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2018-20
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2018-20